{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शनिवार 01 अगस्त 2026
श्रावण कृष्ण 03 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 308
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	78,094.64
निफ्टी	-	24,383.60
सोना	-	1,52,910
चांदी	-	2,35,000
डॉलर	-	95.43

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

पेपर लीक के बाद अब चढ़ावा चोरी : हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का 10वां दिन

लोकसभा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित, संसद परिसर के बाहर विपक्ष का राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का किया नाट्य मंचन

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर-पार की स्थिति बन गई है। पहले नीट पेपर लीक और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठकार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सदन में नीट पेपर लीक मामले में सरकार से चर्चा करने की मांग की थी। वहीं सपा ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की है। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसको लेकर संसद की दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग करता रहा। हालांकि, इस बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। उसके बाद संसद की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधु के कपड़े पहनकर शुक्रवार को संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी को दिखाने वाला प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अवधेश प्रसाद दानपेटी में सांकेतिक रूप से चढ़ावा डालते नजर आए। प्रदर्शन के हिस्से के रूप में पप्पू यादव उन पैसों को अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दानपेटी में प्रतीकात्मक रूप से रुपए डाले। इसके बाद पप्पू यादव दानपेटी लेकर भागने का अभिनय करने लगे, जबकि अन्य सांसदों ने उन्हें रोकने और पकडने् की सांकेतिक कार्रवाई की। इस दौरान सांसदों ने मजाकिया अंदाज में उनकी पिटाई करने का भी अभिनय किया। प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव ने कहा, हमें लगा कि पैसे लेकर भाग जाएंगे, लेकिन सपा सांसदों ने पकड़ लिया। अब कह रहे हैं कि फांसी चढ़ा देंगे।

विपक्षी सांसदों के इस प्रदर्शन पर आसंदी ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि संसद परिसर या सदन के अंदर शालिनता का पालन करें, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में हिस्सा नहीं लेने को लेकर विपक्ष पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस अहम विधेयक पर चर्चा चाहती थी। रिजिजू ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने आपको संसद भेजा है, वे आपसे जवाब मांगेंगे। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि वे भविष्य में विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लें, न कि सदन की कार्यवाही बाधित करें। दिलीप सैकिया ने भी कहा कि विपक्ष के सहयोग के बिना विधेयक पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सांसद पप्पू यादव बने चढ़ावा चोर!

संत समाज ने जताई नाराजगी

संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन पर संत समाज ने नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे साधु-संतों और भगवा वस्त्र का अपमान बताया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्रवाई की मांग की। दरअसल, विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भगवा वस्त्र पहने सांसद पप्पू यादव प्रतीकात्मक रूप से चढ़ावा बटोरते नजर आए। जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसद चढ़ावा चढ़ाते नजर आए। इस दौरान कई अन्य विपक्षी सांसद भी मौजूद रहे। साधुओं के भेष में विपक्ष के प्रदर्शन पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को सरकार या भाजपा का अधिकार है। लेकिन साधु-संतों क वेशभूषा का उपयोग कर पूरे संत समाज पर चोरी का आरोप लगाने जैसा संदेश अनुचित है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि इस तरह का प्रदर्शन संत परंपरा और भगवा वस्त्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा, अगर इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही है। जो भी कानूनी फैसला होगा, संत समाज उसे स्वीकार करेगा। सरस्वती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी दोहराई।

विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की

इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सदन की कार्यवाही में अमित शाह की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए। सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए- अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह सदन में आओ और चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़।

मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 20 जुलाई को जब छात्र-प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तब कोई फायरिंग नहीं हुई थी। एक एक्स पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री ने संसद में साफ झूठ बोला। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीडिया के सामने पेलेट गन के शिकार से मिले। ऐसी फायरिंग के शिकार लोगों के बारे में अनगिनत मीडिया रिपोर्ट्स हैं और हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं कि पीड़ित ऐसी फायरिंग से घायल हुए थे। सरकार संसद में ऐसे साफ झूठ बोलकर बच नहीं सकती। मंत्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

राहुल बोले- युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती सरकार

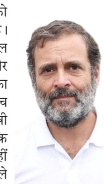

नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जेन-जेड यानी युवा पीढ़ी को डराकर चुप नहीं करा सकती। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तथा सोशल मीडिया खातों को बंद कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह देश के अतीत की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि भारत का भविष्य युवाओं से जुड़ा है। उन्होंने केंद्र से युवाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की बात कही। दरअसल, नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

खास खबर

उज्जैन में भारत का पहला डिजिटल सर्प इंफोटेनमेंट पार्क

उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में भारत का पहला अनोखा स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क शुरू हो गया है, जो सांपों के प्रति लोगों के डर को ज्ञान और रोमांच में बदलने का काम करेगा। यह अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस पार्क भारत सहित दुनियाभर की सर्प प्रजातियों की रोचक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और यह स्थल बच्चों, युवाओं व पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा। इस पार्क में प्रवेश करते ही पर्यटकों को जंगल जैसा अद्भुत अनुभव मिलता है। यहां देश-विदेश में पाई जाने वाली लगभग 4600 सर्प प्रजातियों की पहचान, स्वभाव, रहन-सहन और विशेषताओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

5 आतंकी हैंडलर्स की संपत्तियां जब्त की

जम्मू। जम्मू पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे पांच आतंकी हैंडलर्स की संपत्तियां जब्त की हैं। रियासी पुलिस ने माहौर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान इन आतंकी हैंडलर्स की जानकारी मिली थी। जांच में सबूत मिले हैं कि पांचों आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भाग गए थे और वहीं से आतंकी हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। यह भी पता चला कि वे इन संपत्तियों को बेचने की फिराक में थे। जिससे कि उससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों की फंडिंग में किया जा सके।

पत्नी और तीन बेटों की हत्या पर पति को फांसी, 2 लाख जुर्माना भी

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जघन्य हत्याकांड के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने पत्नी और तीन मासूम बेटों की गला रेतकर निर्मम हत्या करने वाले जितेंद्र कुशवाहा को फांसी की सजा के साथ-साथ दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह वीभत्स घटना 26 अगस्त, 2021 को कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर के गुरमिया गोपाल टोला में घटी थी। दोषी जितेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी लीलावती और बेटों आकाश (8), विकास (6) व रिंकू (4) का धारदार हथियार (सब्जी काटने वाला पहसुल) से गला रेतकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मृतक लीलावती के पिता रामजीत कुशवाहा ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और धारदार हथियार भी बरामद किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही हुई।

रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी का बड़ा एक्शन, 782 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट कंपनी रॉहिया डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 782.36 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। मामला करीब 4,600 घर खरीदारों से कथित तौर पर 2,425.99 करोड़ रुपये जुटाने और आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने के वादे से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, यह जांच आर्थिक अपराध शाखा में घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर दर्ज कई प्राथमिकी से शुरू हुई। जांच के दौरान एजेंसी ने रॉहिया डेवलपर्स लिमिटेड, उसके निदेशक नवीन एम. रॉहिया और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।

एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं के नाम पर बड़ी रकम घर खरीदारों से एकत्र की। अब तक की जांच में करीब 2,425.99 करोड़ रुपये की राशि लगभग 4,600 खरीदारों से लिए जाने की बात सामने आई है। मामले में एजेंसी पहले भी संपत्तियां कुर्क कर चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि 28 अप्रैल 2026 को करीब 1,113.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इसके बाद 15 जून 2026 को लगभग 503.48 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2,399.65 करोड़ रुपये हो गया है।

ईडी की यह कार्रवाई उन घर खरीदारों के लिए अहम मानी जा रही है, जो लंबे समय से अपनी रकम और घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।

अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

-दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी की हत्या मामले में अदालत का फैसला

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस मामले को अत्यंत जघन्य बताते हुए सभी दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अंकित शर्मा का अपहरण कर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर कुल 51 चोटों के निशान पाए गए थे, जिनमें 18 घाव धारदार हथियार से किए गए थे।

हालांकि अदालत ने मृत्युदंड देने से इनकार करते हुए कहा कि यह अपराध निस्संदेह अत्यंत क्रूर और अमानवीय था। अदालत ने टिप्पणी की कि मृतक के शव को घसीटकर चांदबाग पुलिया तक ले जाया गया और फिर नाले में फेंक दिया गया, जो अपराध की बर्बरता को दर्शाता है। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि दोषी भविष्य में भी इसी प्रकार के हिंसक अपराध करने की प्रवृत्ति रखते हैं या उनके सुधार की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि दोषियों का पूर्व में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए यह मामला दुर्लभतम से भी दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता, जिसमें मृत्युदंड दिया जा सके।

बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि मृत्युदंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए और इस मामले में प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं की गई है। अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जबकि आपराधिक साजिश के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।

यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 65/2020 से संबंधित है। दंगों के दौरान लापता हुए अंकित शर्मा का शव बाद में चांदबाग पुलिया के निकट एक नाले से बरामद हुआ था। मार्च 2023 में अदालत ने ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित कई गंभीर आरोप तय किए थे। अब अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : प्रदूषण फैलाओ और जुर्माना भरो की नीति पर लगाम

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रदूषण फैलाओ और जुर्माना भरो की संस्कृति को पूरी तरह से नकारते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द किया है, जिसके जरिए बिना पर्यावरण मंजूरी के शुरू हुए प्रोजेक्ट्स को बाद में नियमित करने का रास्ता निकला गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद अब कोई भी कंपनी या बिल्डर यह सोचकर काम शुरू नहीं कर पाएगा कि वे बाद में जुर्माना भरकर मंजूरी प्राप्त कर लेगा।

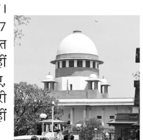

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि 2017 और 2021 की पुरानी व्यवस्थाओं के तहत अब कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा, और भविष्य में बिना नया नियम लाए, केवल प्रशासनिक ज्ञापन (मेमोरेंडम) जारी करके उल्लंघन करने वालों को माफी नहीं मिल सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के मेमोरेंडम को अवैध घोषित किया है,यह बताकर की मोदी सरकार साधारण प्रशासनिक आदेश से वैधानिक नियमों को नहीं बदल सकती। हालांकि, 14 मार्च 2017 को जारी अधिसूचना को सही माना गया, क्योंकि वह केवल छह महीने की एक वन-टाइम माफी योजना थी। जनहित के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे एम्स अस्पताल, हवाई अड्डे और सिंचाई परियोजनाओं को सुरक्षा दी गई है, ताकि उन्हें ढहाने से पर्यावरण का और अधिक नुकसान न हो। साथ ही, सरकारी प्रोजेक्ट्स में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों की निजी जिम्मेदारी तय होगी और उनकी सैलरी से जुर्माना वसूला जा सकता है। इस फैसले का मध्य प्रदेश पर भी गहरा असर होगा, जहां इसतरह के कई मामले लंबित हैं जिनमें बाद में मंजूरी के लिए आवेदन किया गया था। अब ये प्रोजेक्ट्स संकट में पड़ जाएंगे।

विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता विवाहित बेटियों को पात्र मानकर अन्य विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बेटी और बेटे के बीच इस प्रकार का वर्गीकरण असंवैधानिक है और कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बिहार सरकार की 10 दिसंबर 2014 की नीति की संबंधित शर्त को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने उस महिला की अपील स्वीकार कर ली, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह न तो तलाकशुदा थी और न ही परित्यक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह पहले भी कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि बेटी और बेटे के बीच किया गया कोई भी भेदभाव संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। अदालत ने कहा कि केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता विवाहित बेटियों तक पात्रता सीमित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

पीठ ने बिहार सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के बाद बेटी सामान्यत: अपने मायके से संबंध समाप्त कर पति के घर रहने लगती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि विवाह के बाद बेटी अपने मायके से पूरी तरह अलग हो जाती है।

मामला एक महिला से संबंधित था, जिसने अपने सरकारी कर्मचारी पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उसके मामा ने आपत्ति दर्ज कराई थी और राज्य सरकार की नीति के अनुसार केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता विवाहित बेटियां ही इस सुविधा की पात्र थीं। बाद में महिला के मामा ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अपने मायके में रह रही है तथा उसकी मां और भाई ही उसका सहारा हैं। इसलिए केवल तकनीकी आधार पर उसके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता।

भारतीय रेल का ऐतिहासिक कारनामा, वंदे भारत से पहली बार हुआ जीवित हृदय का परिवहन

अहमदाबाद। भारतीय रेल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 31 जुलाई 2026 को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जीवित हृदय का सफलतापूर्वक परिवहन किया। सूरत से अहमदाबाद तक हृदय को ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रलङ्कगांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस से सुरक्षित एवं निर्धारित समय में पहुंचाया गया। इस हृदय का प्रत्यारोपण यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में किया जाएगा।

यह अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध जीवनरक्षक अभियान भारतीय रेल, गुजरात राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा चिकित्सा टीमों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण रहा।

हृदय को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए आरपीएफ और गुजरात राज्य पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके माध्यम से अंग को निर्धारित समयसीमा के भीतर अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि प्रत्यारोपण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, वेद प्रकाश ने कहा, 卐यह भारतीय रेल के लिए अत्यंत गर्व और संतोष का क्षण है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से एक जीवित हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया गया। ऐसे जीवनरक्षक मिशन में समय का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। भारतीय रेल, आरपीएफ, गुजरात राज्य पुलिस और चिकित्सा टीमों के बीच उत्कृष्ट समन्वय ने इस अभियान को सफल बनाया। किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में भारतीय रेल की भूमिका निभाना हमारे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा और मानवता का सर्वोच्च दायित्व है।卐

वंदे भारत एक्सप्रेस की गति, समयपालन और विश्वसनीयता ने इस जीवनरक्षक अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय रेल केवल यात्रियों और माल के परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन एवं जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रही है।

इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता में भारतीय रेल के विभिन्न विभागों, आरपीएफ, गुजरात राज्य पुलिस, चिकित्सकों, अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों तथा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी एजेंसियों के बीच प्रभावी एवं त्वरित समन्वय के कारण यह चुनौतीपूर्ण जीवनरक्षक अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रेल की त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाओं के साथ-साथ मानव जीवन की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

कुछ ना कहना

केवल लांजी ही नही, बल्कि बालाघाट नगर में भी चल रहा, डबल मनी का खेल

दुगनी रकम के लालच मे,कई लोगो से कराया निवेश, डूबे पैसे : अब पैसे वापस पाने निवेशक, काट रहे सरकारी कार्यालयों के चक्कर: निवेशकों ने आईजी से की मुलाकात,सौपा ज्ञापन, रकम वापस कराने की लगाई गुहार : निवेशकों का करीब 15 से 20 करोड़ रु डूबने की कही जा रही बात : आरोपी रकम लेकर 2 वर्षो से चल रहा फरार, अलग अलग स्किम बताकर निवेशकों को ठगा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। डबल मनी मामले का जब भी नाम सामने आता है तो हर किसी के जहन में लांजी, बोलेगाव व किरनापुर के दृश्य के साथ साथ, इन सब का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकराने ही याद आता है। लेकिन बात अगर डबल मनी का लालच देकर निवेश कराने की करें, तो डबल मनी के लालच का यह खेल केवल लांजी क्षेत्र ही, नहीं बल्कि बालाघाट नगर में भी लंबे समय से चल रहा है। जहां तरह-तरह के प्रलोभन देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए निवेश कराए और अब निवेश कराने वाला व्यक्ति, रकम वापस करे बगैर ही, फरार हो गया है। जिसके चलते निवेशक परेशान हो चुके हैं, वही अब निवेशकों के सब्र का बांध भी टूट चुका है।अब निवेशक रकम वापसी की गुहार लगाने सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।बावजूद इसके भी पुलिस अब तक आरोपी का पता नहीं लगा पाई है और ना ही अब तक निवेशकों की रकम उन्हें वापस मिल पाई है।पिछले कुछ वर्षों से लगातार सामने आ रहे इन्हीं मामलों के बीच डबल मनी के नाम पर नगर में भी 15 से 20 करोड रुपए का निवेश कराने और मोटी रकम लेकर फरार हो जाने का एक ताजा मामला नगर के वार्ड नं 33 से सामने आया है।जहां के स्थानीय और अन्य निवेशकों ने वार्ड नं 33 निवासी विनोद माहुले पर निवेशकों का करीब 15 से 20 करोड़ रु लेकर फरार होने का आरोप लगाया है।निवेशकों द्वारा मामले की शिकायत आईजी से करते हुए उनकी रकम उन्हें वापस दिलाने और मामले में उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई गई है ।

करीब 15 से 20 करोड रुपए का निवेश की कही जा रही बात

पिछले दिनों लांजी क्षेत्र में सामने आए डबल मनी घोटाले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब बालाघाट नगर में भी इसी तरह के बड़े निवेश घोटाले का मामला चर्चा का विषय बन गया है। जहां शहर के सैकड़ों लोगों ने रकम को कम समय में दोगुना करने के लालच में अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी निवेश कर दी, लेकिन अब न तो मूलधन वापस मिल रहा है और न ही किसी प्रकार का लाभ। बताया जा रहा है कि इस मामले में करीब 15 से 20 करोड़ रुपये निवेशकों के फंसने की आशंका है।

अलग अलग स्कीमें बताकर कराया निवेश,तो किसी को बताई मजबूरी मांगा उधार

निवेशकों के अनुसार आरोपी ने अलग-अलग निवेश योजनाओं और आकर्षक स्कीमों का झांसा देकर लोगों का विश्वास जीता। शुरुआत में कुछ लोगों को समय पर भुगतान कर भरोसा कायम किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने लाखों रुपये तक निवेश कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद भुगतान बंद हो गया और आरोपी अचानक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब दो वर्षों से फरार है, जिससे निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।

एक नजर में

दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए गए।

करीब 15 से 20 करोड़ रुपये निवेशकों के फंसने की चर्चा।

आरोपी करीब दो वर्षों से फरार, निवेशकों को नहीं मिली रकम।

राशि वापस दिलाने की मांग को लेकर निवेशकों ने आईजी से मिलकर सौंपा ज्ञापन।

अलग-अलग निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को बनाया गया शिकार।

सरकारी कार्यालयों और पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर हुए निवेशक

निवेशक सरकारी कार्यालयों के काट रहे चक्कर

उधर अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए निवेशक पिछले लंबे समय से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कई बार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद अब तक उन्हें कोई ठोस

राहत नहीं मिल सकी है। इसी के चलते निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की।

हमारी रकम वापस कराई जाए

निवेशकों ने बताया कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, मकान निर्माण और भविष्य की जरूरतों के लिए वर्षों की बचत निवेश की थी। अब रकम फंस जाने से कई परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उधार लेकर भी निवेश किया था, जिससे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है।निवेशकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया जाए, पीड़ितों की सूची तैयार कर शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए वही इस प्रकार की फर्जी निवेश योजनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह की ठगी का शिकार न बने।

लांजी के डबल मनी का स्वरूप है यह ठगी- निवेशक

ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्रेम नगर निवासी ईशुलाल कोरे और वार्ड नंबर 33 निवासी सुरेश सिंह बघेल सहित अन्य ने संयुक्त रूप से बताया कि उनके मोहल्ले में विनोद माहुले नाम का एक व्यक्ति निवास करता था, वह अपने मकान का निर्माण कर रहा था जिसके लिए किसी से उसने 20 लाख किसी से 60 लाख तो अन्य लोगों से लाखों रुपए लिए थे प्लाटिंग का धंधा करता था इसीलिए किसी को प्लांट किसी को खेती देने की बात कही थी, बदले में चैक भी दिया था। रिलेशन में होने और मोहल्ले पड़ोस का व्यक्ति होने के चलते लोगों ने उस पर विश्वास जाताया और रकम दे दी, करीब 15 से 20 करोड रुपए निवेशकों के लेकर पिछले दो सालों से वह फरार है जिस तरह लांजी में डबल मनी का मामला चल रहा था यह भी उसी का स्वरूप है। क्योंकि कई लोगों को 4 प्रतिशत अधिक रकम वापस करने का प्रलोभन भी उसके द्वारा दिया गया था। हमने कई बार एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौपा है,आईजी साहब को भी 17 मार्च को ज्ञापन दिया था लेकिन अब तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है।आरोपी ने रकम के बदले जो चैक दिए थे वह बाउंस हो गए हैं कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थाई वारंट जारी किया है लेकिन आरोपी अभी पहुच से काफी दूर है।हमारी मांग है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ कर बालाघाट लाया जाए और हमें हमारी रकम वापस दिलाई जाए।

प्लाट बेचते समय कॉलोनी नाईजर ने किए थे तरह तरह के वादे, नही कराया काम

नाली निर्माण में बरती जा रही अनियमितता वार्डवासियों ने लगाया आरोप

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। अक्सर कॉलोनी नाईजर सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी का निर्माण और तरह-तरह की सुविधाए देने का प्रलोभन देकर लोगों को प्लाट बेच देते है।लेकिन वादों के मुताबिक कॉलोनी में सुविधाए नही बनाई जाती,जिसका खामियाजा वहां प्लाट खरीदकर मकान बनाने को भुगतना पड़ता है।जहा के रहवासी बाद में अक्सर मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर नजर आते हैं।ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 33 अवधपुरी पंवार ले आउट का है।जहां के रहवासियों ने नाली निर्माण गुणवत्ता पूर्वक नहीं किए जाने,व नाली का निर्माण आड़ी तिरछी किए जाने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया है।जिन्होंने नाली निर्माण सही तरीके से किए जाने सहित कॉलोनाइजर से मंगल भवन व गार्डन बनाने की भी मांग की है।बताया गया कि कॉलोनाईजर द्वारा प्लाट विक्रय करते समय मंगल भवन व गार्डन बनाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक इनका निर्माण नहीं किए जाने से वार्डवासी नाराज है।जिन्होंने वादों के मुताबिक कार्य करने की मांग की है।

सकरी सड़क से होंगी परेशानी

स्थानीय रहवासियों ने बताया कि जब हम मकान निर्माण कर रहने लगे थे तब पहले सडक की समस्या थी।लेकिन अब पक्की सडक का निर्माण हो गया है। पहले उक्त सडक के लिए 30 फीट की जगह दी गई थी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा सडक पर ही अतिक्रमण करने से सडक सकरी हो गई है। अब बारिश के समय नपा द्वारा पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है। जिससे स्कूली बच्चों व आम लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है।

प्लाट बेचते समय मंगल भवन व गार्डन बनाने की कही थी बात- अमूले

स्थानीय रहवासी आर.सी अमूले ने बताया कि कालोनाईजर द्वारा 16 एकड़ भूमि में 120 लोगों को प्लाट का विक्रय किया है। इस दौरान मंगल भवन व गार्डन के लिए आरक्षित जमीन होने की बात कर मंगल भवन व गार्डन बनाने की बात कही गई थी। लेकिन अब उनके द्वारा अपनी बातों पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि हमें विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि कॉलोनाइजर के द्वारा अनाधिकृत रूप से आरक्षित जमीन भी बेच भी दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि कॉलोनी के नियमों का पालन करते हुए मंगल भवन व गार्डन बनाया जाए।

गुणवत्ता के साथ हो नाली का निर्माण- शेषराम राहंगडाले

स्थानीय रहवासी शेषराम राहंगडाले ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा जो नाली का निर्माण किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। नाली भी आड़ी-तिरछी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां कहीं पर 25 फीट सडक है तो कही 22 फीट ही है। अब नाली बनने से सडक 18 फीट हो गई है। जिससे स्कूली वाहनों के आवा-जाही व बड़े वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होगी। उन्होंनें बताया कि जिन लोगों ने यहां प्लाट लेकर बनाया उनके द्वारा भी सडक की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है इससे कुछ स्थानों पर सडक सकरी हो गई है।

सभी से चर्चा कर समस्या का हल निकाला जा रहा है- योगेश बिसेन

इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष एंव वार्ड पार्षद योगेश बिसेन ने बताया कि यहां के रहवासियों की नाली निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग थी। जिससे पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है। यहां एक शासकीय भूमि है जो विवाद में है। जहां पानी भरा रहता है जिससे गंदगी भी रहती है। इससे नाली निर्माण किया जा रहा था। जिस तरह लोगों ने मकान निर्माण किया है उसकी आधार पर नाली का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। एक व्यक्ति ने जमीन आगे बढ़ा ली है इससे कुछ जगह नाली घुमावदार बन रही है। वार्ड वासियों से चर्चा कर समस्या का हल निकाला जा रहा है।

नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जताई गई नाराजगी

भारत मुक्ति और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भारत मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, किए जाने की मांग की है। सँयुक्त रूप से सौपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने,सहित विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि नीट-यूजी परीक्षा में सामने आई धांधलियों और अनियमितताओं ने देश के करोड़ों विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर किया है, इसलिए इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

विद्यार्थियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले सरकार

संगठन ने नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने, शिक्षा के निजीकरण, विद्यार्थियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और बढ़ती ड्रॉपआउट दर जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा परीक्षा संचालन के लिए एक पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई गई।ज्ञापन में मांग की गई कि ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाया जाए। साथ ही वर्तमान नीट परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा का संचालन एम्स की निगरानी में पारदर्शी तरीके से कराया जाए। इसके अलावा देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने और आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की

भी मांग पदाधिकारियों द्वारा की गई है।

पेपर लीक के दोषियों पर की जाए कड़ी कार्यवाही

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नीट, एसएससी (सीजीएल) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की गई।इसके अलावा संगठन ने विद्यार्थियों के साथ होने वाले शोषण और अवैध वसूली पर रोक लगाने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, देशभर में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने तथा सभी विद्यार्थियों के लिए समान और न्यायसंगत शुल्क (फीस) प्रणाली लागू करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की लगभग 52 प्रतिशत सीटों में की गई कटौती को वापस लेने की मांग करते हुए कहा गया कि इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे।

यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है,बल्कि शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, विश्वसनीयता का है- ठवकर

भारत मुक्ति मोर्चा वरिष्ठ पदाधिकारी रामदास ठवकर ने बताया की यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो सके।आज ज्ञापन के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने और शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक विशाल कुमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम पंचायत हिर्री ने नही अपितु ग्रामीणों ने आपस मे लेन देन कर खरीदी बिक्री की सरकारी भूमि- सरपंच

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत हिर्री के कुछ पंचों ने विगत दिनों जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए सरपंच पर सरकारी भूमि बेचे जाने का आरोप लगाया गया था। जिस पर ग्राम पंचायत हिर्री सरपंच श्रीमति विनिता राजेन्द्र पाराशर ने की गई शिकायत

को पूरी तरह बेबुनियाद,गलत,भ्रामक, निरर्थक एवं ग्राम पंचायत सरपंच की छवि धूमिल करने की साजिश बताया है। इस बाबत जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत हिर्री सरपंच श्रीमति विनिता राजेन्द्र पाराशर ने बताया कि जो आरोप लगाया गया है कि ग्राम की सरकारी भूमि को सरपंच द्वारा बेचा गया वह वास्तव मे चन्द्रशेखर पिता तुलसीराम बनवारी (जाति- कहार निवासी- हिर्री) द्वारा ग्राम के ही राजकुमार नागेश्वर से खरीदी गई हैं। और इस बाबद उन दोनो व्यक्तियों के बीच बाकायदा अनुबंध पत्र भी करार किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत का कोई भागीदारी या मध्यस्थता नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा चंद्रशेखर पिता तुलसीराम बनवारी को मतदाता सूची मे उसका नाम दर्ज़ होने के आधार पर ही नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि चन्द्रशेखर पिता तुलसीराम बनवारी (जाति- कहार निवासी- हिर्री) द्वारा ग्राम के ही राजकुमार नागेश्वर के मध्य हुए भूमि खरीदी बिक्री मे सरपंच और ना ही किसी पंच की भूमिका है। बावजूद कुछ पंचों द्वारा अन्य पंचों एवं ग्राम के लोगो को गुमराह करते हुए एवं उन्हें गलत जानकारी देकर शिकायत पत्र में उनके हस्ताक्षर करवा लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की गई। इस विषय की जांच के दौरान सारे साक्ष्य जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। एवं सरपंच की छवि धूमिल करने वाले लोगों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।

38 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद सहायक शिक्षक अशोक चौहान हुए सेवानिवृत्त

मंगोली कला व खारा में शिक्षक के रूप में निभाया दायित्व, स्कूल स्टाफ ने दी बिदाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक स्कूल मंगोलीकला सहायक शिक्षक के पद पर सेवा दे रहे अशोक कुमार चौहान 31 जुलाई शुक्रवार को सेवानिवृत हो गए है। उनके सेवानिवृत होने पर स्कूल स्टाफ द्वारा बिदाई समारोह का आयोजन कर पुष्प गुच्छ व शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया।बताया गया कि शिक्षक श्री चौहान ने शिक्षा विभाग में 38 वर्षो तक अपनी सेवाएं देने के बाद आज सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में पूरी ईमानदारी व समर्पण के साथ निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निवर्हन किया। इस संबंध में सहायक शिक्षक अशोक चौहान ने बताया कि उन्होंने अपने सेवा काल में 15 वर्ष ग्राम खारा में व 23 वर्ष मंगोली कला प्राथमिक शाला में सेवाएं दी है। इस दौरान उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें संस्कार और अनुशासन की सीख भी दी।उन्होंने बताया कि स्कूल में सभी सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर कार्य किया गया। सभी शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय के शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उसी विद्यालय से उन्होंने अपने कर्तव्य से सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिवार, ग्रामीणों व पूर्व विद्यार्थियों ने श्री चौहान के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य व स्वस्थ जीवन की कामना की।इस दौरान मंगोली प्राथमिक शाला के शिक्षक यू.आर ठाकरे, शिक्षिका श्रीमती छबिला कटरे सहित अन्य स्टॉफ व स्कूली बच्चे एवं उनके परिजन मौजूद रहे।

बालाघाट सिटी न्यूज़

पद्मेश न्यूज
बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

दो दिवसीय जिला शालेय कराटे प्रतियोगिता का समापन आज

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय शालेय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, बालाघाट के सभागार में किया गया। यह प्रतियोगिता 31 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले के विभिन्न विकासखंडों से छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।प्रतियोगिता का शुभारंभ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शरद जोशी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बताया गया कि प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न आयु एवं भार वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगामी संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित किए जाएंगे।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना का विकास करना है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा तथा उन्हें अगले स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।इस अवसर पर क्रीड़ा प्रभारी दीपक गिरी गोस्वामी तथा व्यायाम शिक्षिका सुनीता बिसेन ने प्रतियोगिता के सफल संचालन की जिम्मेदारी निभाई और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।कार्यक्रम को सफल बनाने में व्यायाम शिक्षक हरिस धुवारे, मीना मेश्राम, वीना चौधरी, ज्योति पंचेश्वर एवं आशा सुल्लखे का विशेष सहयोग रहा। वहीं कराटे प्रशिक्षकों दिनेश कोरे, कृष्णदास गोंडुडे, संतोष पारधी, प्रवीण नन्हेट, आकाश झा, आशीष बाघ, लकी मरावी, संजू मेश्राम, शुभम मनेश्वर, राकेश वरकड़े, गणेश बोढे, प्रमोद शरणागत एवं जय ठाकरे ने प्रतियोगिता के संचालन एवं तकनीकी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रसूता के रेफरल पर फूटा विधायक का गुस्सा, डॉक्टरों की लगाई क्लास

निजी अस्पताल से वापस लाकर पुनः कराया भर्ती जिला चिकित्सालय में, डेढ़ घंटे तक चली जवाब-तलब, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला चिकित्सालय से मरीजों, विशेषकर प्रसूताओं को निजी अस्पतालों की ओर रेफर किए जाने की शिकायतें लंबे समय से उठती रही हैं, लेकिन शुक्रवार को ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हाई-रिस्क बताकर निजी अस्पताल भेज दिया। जैसे ही इसकी जानकारी बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को मिली, वे सीधे निजी अस्पताल पहुंचीं, प्रसूता को वहां से वापस जिला चिकित्सालय लेकर आईं और फिर सिविल सर्जन के कक्ष में संबंधित डॉक्टरों से एक-एक सवाल का जवाब मांगा। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान जिला अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति संभालने में जुटे रहे।

मामला सिवनी जिले के कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुरी निवासी प्रीति गहरवाल का है, जिन्हें 30 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के बाद कई घंटों तक प्रसूता का समुचित परीक्षण नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि न तो समय पर डॉक्टर पहुंचे और न ही आवश्यक उपचार शुरू किया गया। काफी इंतजार के बाद जब प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया तो एनेस्थीसिया डॉ. अश्विनी

भौतेकर ने मरीज को हाई-रिस्क बताते हुए जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने से मना कर दिया और निजी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अचानक निजी अस्पताल जाने के लिए कहा गया। चिकित्सकों द्वारा जोखिम का हवाला दिए जाने से परिवार घबरा गया और प्रसूता को निजी अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान पूरे घटनाक्रम की जानकारी विधायक अनुभा मुंजारे तक पहुंची। विधायक ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निजी अस्पताल से प्रसूता को वापस जिला अस्पताल बुलवाया और सीधे सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन के कक्ष में पहुंच गईं। विधायक ने संबंधित स्त्री रोग डॉ. श्रद्धा बारमाटे और एनेस्थीसिया डॉ. अश्विनी भौतेकर को बुलाकर पूरे मामले में जवाब मांगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बैठक के दौरान विधायक ने चिकित्सकों से पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी चिकित्सकीय परिस्थिति थी, जिसके कारण मरीज को सरकारी अस्पताल में उपचार देने के बजाय निजी अस्पताल भेजना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि यदि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं तो फिर मरीजों को निजी अस्पताल क्यों भेजा जा रहा है? बैठक के दौरान विधायक ने डॉक्टरों के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाला प्रत्येक मरीज सम्मान और संवेदनशील व्यवहार का अधिकारी है। मरीज और उनके परिजनों को पहले पूरी चिकित्सकीय स्थिति समझाई जानी चाहिए, न कि उन्हें डराकर निजी अस्पताल जाने के लिए मजबूर किया जाए। विधायक ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार बड़ी उम्मीद लेकर जिला अस्पताल आते हैं, लेकिन यदि उन्हें हर बार निजी अस्पताल का रास्ता दिखाया जाएगा तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। करीब डेढ़ घंटे तक चली चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रसूता के ऑपरेशन से पहले चिकित्सकों द्वारा परिजनों से उच्च जोखिम को लेकर सहमति पत्र मांगा गया था, लेकिन प्रारंभ में परिजनों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाद में विधायक की मौजूदगी में दोबारा काउंसिलिंग की गई और परिजन सहमति पत्र देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद निर्णय लिया गया कि प्रसूता का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में ही किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. निलेश जैन ने स्वीकार किया कि उन्हें प्रारंभ में यही जानकारी थी कि मरीज का ऑपरेशन अस्पताल में ही किया जाएगा। बाद में पता चला कि एनेस्थीसिया डाक्टर द्वारा हाई-रिस्क बताते हुए ऑपरेशन करने से इंकार किया गया था। उन्होंने कहा कि मरीज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन अब परिजनों की सहमति मिलने के बाद जिला अस्पताल में ही ऑपरेशन कराया जाएगा।

अस्पताल को रेफरल सेंटर बनाकर नहीं चलाया जा सकता- अनुभा

मीडिया से चर्चा में विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। लंबे समय से जिला अस्पताल के खिलाफ मरीजों को निजी अस्पताल रेफर करने, पर्याप्त जानकारी नहीं देने और संवेदनहीन व्यवहार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज को वास्तव में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हो तो रेफर करना उचित है, लेकिन बिना पर्याप्त कारण मरीजों को निजी अस्पताल भेजना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला अस्पताल को रेफरल सेंटर बनाकर नहीं चलाया जा सकता। सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करती है, आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराती है और ऑपरेशन थिएटर तैयार करती है, फिर भी यदि मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जा रहा है तो यह गंभीर प्रशासनिक और चिकित्सकीय प्रश्न है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की शिकायतें दोहराई गईं तो मामले को शासन स्तर तक उठाकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।

43 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को भावभीनी विदाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट में शुक्रवार को गणित विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति अवसर पर भावभीना विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महाविद्यालय परिवार, पूर्व एवं वर्तमान प्राध्यापक, कर्मचारी, छात्र-छात्राओं तथा गणमान्य नागरिकों ने उनके 43 वर्षों के उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योगदान को याद करते हुए सम्मानपूर्वक विदाई दी।समारोह के दौरान प्रो. श्रीवास्तव को शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रशस्ति-पत्र का वाचन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने लंबे सेवाकाल में न केवल गणित विषय के उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में पहचान बनाई, बल्कि महाविद्यालय के प्रशासनिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में महाविद्यालय ने अनेक उपलब्धियां हासिल कीं और शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक किया निर्वह

आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं

द्वारा बताया गया कि प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का जन्म 16 जुलाई 1961 को बालाघाट में हुआ। उन्होंने वर्ष 1983 में शासकीय सेवा में प्रवेश किया और 31 जुलाई 2026 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।इस दौरान उन्होंने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दमोह सहित विभिन्न संस्थानों में सेवाएं देने के बाद शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में गणित विभागाध्यक्ष, प्रभारी प्राचार्य तथा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।समारोह के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी।

शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का माध्यम है- प्रो श्रीवास्तव

आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में प्रो. श्रीवास्तव ने महाविद्यालय परिवार, सहयोगी प्राध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का माध्यम है।उन्होंने सभी से शिक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

मकान विवाद में चाचा ने भतीजे को लोहे के पाइप से मारकर किया गया

भतीजा जिला अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सरेखा में मकान विवाद को लेकर एक युवक के साथ उसके चाचा एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में घायल युवक लेखराम पिता रूपचंद राजूरकर 35 वर्ष ग्राम सरेखा निवासी को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सरेखा निवासी लेखराम राजूरकर मजदूरी का कार्य करता है। उसका अपने चाचा लक्ष्मीचंद राजूरकर के साथ मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।बताया गया कि 30 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे लेखराम एक गुपचुप की दुकान पर था। इसी दौरान उसकी पत्नी दीपाली ने फोन पर सूचना दी कि लक्ष्मीचंद राजूरकर मकान अपने नाम कराने की बात को लेकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। सूचना मिलते ही लेखराम अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की तभी उसके चाचा लक्ष्मीचंद राजूरकर ने कथित रूप से लोहे की पाइप से उस पर हमला कर दिया।आरोप है कि इस दौरान कृष्णा राजूरकर एवं कमलेश राजूरकर ने भी गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थरों से मारपीट की। हमले में लेखराम के हाथ, पैर और घुटने में चोटें आईं।घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल लेखराम को उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर मामले को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को भेज दिया है।

जिला अस्पताल के सामने सड़ांध का साम्राज्य

नालियों की सफाई नहीं होने से जमा हुआ मलबा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट के ठीक सामने सड़क किनारे बनी नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से बरसाती पानी की निकासी बाधित हो गई है। नालियों में गंदगी और मलबा जमा होने के कारण वहां से उठ रही दुर्गंध अब अस्पताल परिसर तक फैलने लगी है। इससे मरीजों, उनके परिजनों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के सामने स्थित नालियों की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। लेकिन लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण नालियां कचरे और मलबे से पट चुकी हैं। परिणामस्वरूप बरसात का पानी रुक रहा है और सड़ांध फैलने लगी है। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी व्याप्त है।अस्पताल के दूसरे प्रवेश द्वार के सामने भी नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां से प्रतिदिन हजारों मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और आम नागरिक गुजरते हैं।जिन्हें दुर्गंध के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या की ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं गया है।गौरतलब है कि जिला अस्पताल अवंतीबाई चौक से बूढ़ी रोड को जोड़ने वाले व्यस्त मार्ग पर स्थित है।जहां दिनभर यातायात बना रहता है। ऐसे में सड़क किनारे जमा गंदगी न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है बल्कि अस्पताल आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनती जा रही है। बरसात के मौसम में इस तरह की गंदगी से संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ गई है।स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि अस्पताल परिसर के आसपास की नालियों की तत्काल सफाई कराई जावे ।जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर नियमित सफाई व्यवस्था की जाए, ।ताकि मरीजों और आम नागरिकों को इस समस्या से राहत मिल सके।

गुरु पूर्णिमा पर पूर्व छात्रों ने दी छात्रवृत्तियों की सौगात

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, बालाघाट में आयोजित समारोह में वर्ष 1981 बैच के पूर्व छात्र थान सिंह नाहर ने अपने पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद नाहर की स्मृति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 44 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति का वितरण किया।

समारोह की मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मोनिका पटेल थीं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी कुमार उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं पूर्व छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री विनोद नेमा ने स्वर्गीय अधिवक्ता श्री एम.पी. राव की स्मृति में लगभग 12.80 लाख रुपए की एफडी विद्यालय को समर्पित करने की घोषणा की, जिसके ब्याज से प्रतिवर्ष लगभग 85 हजार की छात्रवृत्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। वहीं पूर्व छात्र श्री कमलेश सिंह ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए क्रमशः 3,500 रुपए एवं 05 हजार रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्य अतिथि श्रीमती मोनिका पटेल ने विद्यार्थियों को मेहनत से अध्ययन कर ऐसी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। प्रभारी प्राचार्य शरद ज्योतिषी ने पूर्व छात्रों के इस योगदान को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी बताते हुए सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

भावुक माहौल में कलेक्टर मृणाल मीना को दी गई विदाई, अधिकारियों ने सराहा दो वर्षों का कार्यकाल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। राज्य शासन द्वारा बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना का स्थानांतरण छतरपुर जिले के कलेक्टर पद पर किए जाने के बाद गुरुवार 30 जुलाई को जिला मुख्यालय में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। आयोजित विदाई समारोह में प्रशासन, पुलिस, वन एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री मीना के नेतृत्व, कार्यशैली और जिले के विकास में उनके योगदान की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह में बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार, पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे एवं श्री डी.पी. बर्मन, वन मंडलाधिकारी नित्यानंदम एल एवं रेशम सिंह धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, मायाराम कोल, श्री विजय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भार्गव एवं श्री निहित उपाध्याय, नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी, एसडीएम अर्पित गुप्ता, कार्तिकेय जायसवाल, श्रीश प्यासी, आदित्य नारायण तिवारी, गोपाल सोनी, श्री कमल सिंहसार, सभी तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि मृणाल मीना ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों वाले बालाघाट

जिले में लगभग दो वर्षों तक उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए जिले को नई पहचान दिलाई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मीना छतरपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में भी अपनी कार्यकुशलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन ने कहा कि श्री मीना का बालाघाट से जाना जिले के लिए निश्चित रूप से क्षति है, लेकिन छतरपुर जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना श्री मीना की विशेषता रही है और वे नई जिम्मेदारियों का भी उसी दक्षता से निर्वहन करेंगे।

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि श्री मृणाल मीना के कार्यकाल में बालाघाट ने नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में सुरक्षा बलों के साथ-साथ कलेक्टर श्री मीना की दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने वाली सोच का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वयं गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए।

विदाई समारोह में भावुक होते हुए कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने कहा कि उन्हें बालाघाट में एक समर्पित और सक्षम अधिकारियों की टीम के साथ कार्य करने का अवसर मिला, जिसके कारण जिला अनेक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में अग्रणी रहा। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हालांकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने मीडिया के सहयोग की भी सराहना की तथा अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक कार्यों के दौरान यदि कभी सख्ती बरती गई हो तो उसे केवल कार्य के हित में समझें, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या दुराग्रह नहीं रहा।

बैहर एसडीएम श्री अर्पित गुप्ता एवं वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल ने कहा कि श्री मीना ने सदैव अधिकारियों पर विश्वास जताया, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दिया तथा गलतियों से सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में कार्य करना उनके प्रशासनिक जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव रहा। समारोह के अंत में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कलेक्टर श्री मृणाल मीना को स्मृति-चिन्ह एवं शुभकामनाएं भेंट कर उनके सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विदाई के दौरान भावुक वातावरण रहा और उपस्थित अधिकारियों ने उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 05 अगस्त को

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 05 अगस्त दोपहर 01 बजे जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार करेंगें। बैठक में विभिन्न बिंदुओ पर चर्चा की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ ने संबंधित अधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। जिला पंचायत के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है।

सड़क या दलदल?

बघोली के गोंडी मोहल्ला से कटंगटोला (टेकाड़ी ला.) मार्ग कीचड़ में तब्दील, आवागमन बाधित

मुख्य मार्ग बारिश में हुआ खस्ताहाल, स्कूल वैन और एंबुलेंस का पहुंचना हुआ नामुमकिन, जिम्मेदार मौन

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय से महज 5 किमी. दूर स्थित ग्राम पंचायत बघोली के गोंडी मोहल्ला से कटंगटोला (टेकाड़ी ला.) पहुंच मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग ढाई किमी लंबा यह मार्ग बारिश के मौसम में पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जबकि ग्रामीणों के लिए अपने गांव तक पहुंचने का यही एकमात्र मुख्य रास्ता है, जो अब हादसों का कारण बन रहा है। कीचड़ इतना अधिक है कि पैदल चलना भी दूभर हो गया है। बच्चों की स्कूल बस-वैन गांव तक नहीं पहुंच पा रही है और ग्रामीण आये दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बार-बार शासन-प्रशासन और पंचायत का ध्यान आकर्षित करवाने के बावजूद समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणजनों ने शासन-प्रशासन से पक्की सड़क का निर्माण करवाने की मांग की है ताकि कीचड़नुमा सड़क से आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर अभाव

आपकों बता दे कि बघोली के गोंडी मोहल्ला से कटंगटोला (टेकाड़ी ला.) पहुंच मार्ग का करीब 10 से 15 वर्ष पूर्व मरम्मत कार्य करवाया गया था। उसके बाद से किसी भी तरह का मरम्मत कार्य नही करवाया गया है। इस तरह से रख-रखाव के अभाव में अब यहां सड़क का नामोनिशान मिट चुका है। बारिश का पानी जमा होने से सड़क पर गहरे गड्डे बन गये है और सड़क के चारों तरफ फैला कीचड़ हादसे को न्योता दे रहा है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। जबकि इस मार्ग से रोजाना गोंडी मोहल्ला और कटंगटोला के सैकड़ों ग्रामीण तथा आदिवासी परिवार आवागमन करते हैं। रोजाना के कामकाज, कृषि कार्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह सड़क ही मुख्य माध्यम है। बारिश के दिनों में फिसलन और कीचड़ के कारण कई स्कूली बच्चे फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। इसके अलावा बीमारों और गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जबकि ग्रामीणजनों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार पक्की सड़क के निर्माण की गुहार लगा चुके है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और वे थक-हारकर अब ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद भी उनकी कोई सुनाई नही होने से ग्रामीणजनों में रोष व्याप्त है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि जब से इस क%ची सड़क का निर्माण हुआ है, उसके बाद से किसी तरह का कोई भी मरम्मत कार्य या नवीन सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। जिसकी वजह से यह सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है और बारिश का पानी जमा होने से सड़क पर गहरे गड्डे बन गये हैं। वहीं सड़क खराब होने से आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यदि गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाये या किसी गर्भवती महिला के लिए जननी एक्सप्रेस बुलाना हो तो सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि पक्की सड़क का जल्द निर्माण करवाये।

साइकिल अनियंत्रित होने से कपड़े होते हैं खराब- महेंद्र

छात्र महेंद्र कंगाली ने बताया कि सड़क खराब हो जाने से जब हम साइकिल से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो कीचड़ में साइकिल अनियंत्रित होकर फिसल जाती है। कई बार हम गिर जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े और किताबें पूरी तरह खराब हो जाती हैं। ऐसे में हमें वापस घर लौटना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण हमारी पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है और स्कूल जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पक्की सड़क का निर्माण होना चाहिए।

सड़क खराब होने से आवागमन में हो रही परेशानी - सुनीता

श्रीमती सुनीता पटले ने बताया कि सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, जिससे आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में स्कूली ब%चे कीचड़ में गिरते-पड़ते स्कूल जाने को मजबूर हैं। रास्ता इतना खराब है कि ब%चों को लेने आने वाली स्कूल वैन घरों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही सड़क कीचड़ एवं गड्डों में तब्दील हो चुकी है, जबकि इस गंभीर समस्या से कई बार पंचायत को अवगत करवा चुके है लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे ग्रामीणजनों मे आक्रोश व्याप्त है। श्रीमती पटले ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क के खस्ताहाल के कारण सभी को परेशानी हो रही है इसलिए शासन-प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क का नवीन पक्का निर्माण करवाये ताकि लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

न मरम्मत हुई, न ही बनी नवीन सड़क - रंजीत

रंजीत गौतम ने बताया कि जब से इस रास्ते का निर्माण (कच्चा मार्ग) बना है, तब से लेकर आज तक न तो यहां कोई पक्का निर्माण कार्य करवाया गया और न ही कभी कोई मरम्मत की गई है। हर साल बारिश में यह मार्ग दलदल बन जाता है। सड़क की समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन स्थिति जस की तस है। श्री गौतम ने बताया कि अगर गांव में कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाये तो खराब सड़क की वजह से गांव तक एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, स्कूली बसें रास्ते में ही रूक जाती हैं। इसलिए प्रशासन या तो जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाये या पक्की सड़क का निर्माण करवाये नही तो ग्रामीणजन कठोर कदम उठाने बाध्य होगें।

इनका कहना है-

मेरे द्वारा बरसात पूर्व इस सड़क की समस्या से क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को अवगत करवाया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़कर इस सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।

अरशद पापा पटेल
सरपंच
ग्राम पंचायत बघोली।

उत्कृष्ट विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व

गुरूजनों के सम्मान के साथ 'गुरू पूर्णिमा पखवाड़े का हुआ भव्य समापन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को 'महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व' का आयोजन कर गत दिवस से चल रहे 'गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा' कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षा समिति के सभापति किशोर पालीवाल, समाजसेवी गिरीश पाठक, अनीता अग्रवाल एवं अय्यूब भारती की विशेष उपस्थिति तथा विद्यालय के प्राचार्य सनत दुबे की अध्यक्षता में हुआ। अतिथियों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती और महर्षि सांदीपनि के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्र%वलित किया। समारोह के दौरान शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक पूरनलाल स्वामी, बी.एम. शर्मा एवं शिक्षिका उर्मिला नागेश्वर को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने गुरू की महिमा पर आधारित एक से बढ़कर एक कविताएं, श्लोक एवं लघु लेख का सुंदर वाचन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा समिति के सभापति किशोर पालीवाल ने विद्यार्थियों को गुरू के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के गुरू महर्षि सांदीपनि के आदर्श जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके बताये मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर शिक्षिका श्रीमती त्रिवेणी बिसेन, संवेद अग्रवाल, ललित ब्रम्हे, सुनील बिसेन, श्रीमती वीणा तितरमारे, पारस रहांगडाले, अमन अवधिया, ब्रजेश बिसेन सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महाविद्यालय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर साहित्यिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शक प्रकोष्ठ के अन्तर्गत शुक्रवार को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर साहित्यिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेमचंद के साहित्य, उनके सामाजिक सरोंकारो तथा मानवीय मूल्यों से परिचित करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. देवराज चौरे ने अपने व्याख्यान में कहा कि प्रेमचंद का साहित्य वर्तमान समय में उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि उन्होने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना, उनकी रचनाएँ विद्यार्थियों को ईमानदारी संवेदनशीलता, समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करती है। मुख्य वक्ता एवं हिन्दी विभाग से श्रीमती अनिभा शरणागत ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद केवल कहानीकार या उपन्यासकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले महान साहित्यकार थे। उनके साहित्य में किसान, मजदूर, महिला, गरीब और वंचित वर्ग के जीवन-संघर्षों का अत्यंत संवेदनशील एवं यथार्थ चित्रण मिलता है। गोदान, गबन, निर्मला, सेवासदन जैसे उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, ईदगाह जैसी कहानियाॅ आज भी समाज को मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देती है। कार्यक्रम प्रभारी नरेश सौलखे के दिशा निर्देश में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन बरवा, प्रदीपकुमार भिमटे, डॉ. निर्मल कीर्ति गेडाम, श्रीमती संध्या भलावे, डॉ. हृशिकेश पटेल, श्रीमती भूमेश्वरी ठाकरे, मनीष शिवहरे, डॉ. आशा कारे, डॉ. आरती विश्वकर्मा, दीपक अहिरवार, पीतम मुरते, यादोराव राजुरकर, व्यंकट नगपुरे, श्रीमती सरिता ऐड़े, रामदयाल मथारे, लकेश गेडाम, श्रीमती वंदना कुर्वे, मिनेश पंचेश्वर, निशांत तलवरे एवं छात्र-छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा।

धान रोपाई का कार्य अंतिम चरण में

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। क्षेत्र में किसानों के द्वारा खरीफ सीजन में लगने वाली धान की फसल के लिए रोपाई का कार्य गत दिवस से किया जा रहा था जो अब अंतिम चरण में है और किसान अब फसल की देखभाल में जुट गये है। पूर्व में क्षेत्र में बारिश नही होने पर जो किसान मानसून की बारिश पर निर्भर थे उनका रोपाई का कार्य प्रभावित हो रहा था परन्तु विगत दिवस हुई तेज बारिश से पुन: उनका कार्य प्रारंभ हो गया था। जो अंतिम चरण में चल रहा है एवं 90 प्रतिशत किसानों का क्षेत्र में धान की फसल की रोपाई का काम लगभग खत्म हो गया है। वहीं खेतों में किसान खाद डालने के साथ ही फसल में लग रही बीमारी की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव कर रहे है ताकि फसल उत्पादन अधिक ले सके। किसानों ने बताया कि खरीफ सीजन में लगने वाली धान की रोपाई का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही यह भी बताया कि जिस तरह से गत दिवस बारिश हुई है। समय-समय पर इसी तरह से करीब 3 माह तक बारिश होना चाहिए ताकि पानी के अभाव में फसल प्रभावित न हो सके। साथ ही यह भी बताया कि समय-समय पर बारिश होते रहती है एवं फसल में किसी प्रकार की बीमारी नही लगती है तो किसान फसल उत्पादन अधिक ले सकता है। किसानों ने सरकार से धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने मांग की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

संघ का गुरूपूजन एवं समर्पण उत्सव 3 को

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय के शांति नगर स्थित लॉन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मंडल लालबर्रा के द्वारा आगामी 3 अगस्त को गुरूपूजन एवं समर्पण उत्सव का आयोजन किया गया है। चर्चा में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मंडल लालबर्रा के खंड कार्यवाहक ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरू माना जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लालबर्रा मंडल में आगामी 3 अगस्त को शाम 6 बजे शांतिनगर स्थित लॉन में गुरूपूजन एवं समर्पण उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। वहीं आयोजक मंडल द्वारा सभी स्वयंसेवकों एवं प्रबुध्दजनों से आग्रह किया गया है कि वे शुभ्रवेश (गणवेश/सफेद वस्त्र) में निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होवें।

शिक्षक मनोज मेश्राम की सुपुत्री प्रिंसी आईआईटी भुवनेश्वर हेतु चयनित

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। तहसील मुख्यालय ग्राम किरनापुर शांतिनगर निवासी शिक्षक दम्पति मनोज मेश्राम एवं श्रीमति पुष्पा मेश्राम की सुपुत्री कुमारी प्रिंसी मेश्राम का आईआईटी भुवनेश्वर में सिविल इंजनिरिंग में चयन हुआ है। प्रिंसी के चयन होने पर उनके पापा मनोज मेश्राम, मम्मी पुष्पा मेश्राम ,बडे पापा विनोद मेश्राम ,बड़ी मम्मी नम्रता मेश्राम, भैया प्रयास प्रिया मेश्राम, प्रज्ञा मेश्राम, शुभम गजभिये, प्रगति गजभिये एवं समस्त सामाजिक बंधुओं ने बिटिया की सफलता पर हर्ष व्यक्त कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाईया प्रेषित की हैं।

पुलिस नहीं कर रही चोरी की एफआईआर विधायक को साथ लेकर थाने पहुंचे पीड़ित

विधायक पटेल टीआई से बोले ईमानदारी से काम करें, अपराधी पकडे लोगों का डर खत्म हो

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में १६ जुलाई से लेकर २९ जुलाई के बीच तीन ड़ी चोरियों की वारदात ने लोगों को डरा दिया है। बावजूद इसके पुलिस चोरियों की एफआईआर नहीं कर रही है। जिससे पीड़त नाराज है २९ जुलाई को वॉर्ड नंबर १ मिश्रा नगर निवासी डॉक्टर योगेन्द्र राहंगडाले के यहां १२ लाख रुपयों से ज्यादा के जेवरात और नगद २ लाख रूपए की चोरी की घटना के दो दिन बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिससे परेशान डॉ.दंपत्ति ने इसकी शिकायत विधायक विवेक पटेल से की। जिसके बाद विधायक विवेक पटेल स्वयं पीड़ित परिवार को साथ लेकर वारासिवनी थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को पीड़ित की एफआईआर लिखने के निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी अनूप कुमार उईके ने विधायक विवेक विक्की पटेल को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द इनकी शिकायत दर्ज कर ली जायेगी।

घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की रिपोर्ट दर्ज- योगेन्द्र राहंगडाले

पीड़ित योगेन्द्र राहंगडाले ने बताया कि २९ जुलाई को हुई चोरी की सूचना वारासिवनी पुलिस को दी गई थी। जिसके बाद पुलिस डॉग स्कॉड और फिंगर प्रिंट की टीम ने घटना स्थल की जांच की। लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की पुलिस बोल रही थी कि पूरी जांच के बाद एफआईआर की जाएगी। जिसके बाद मैने आज मामले को लेकर विधायक से मुलाकात कर उन्हें घटना से अवगत कराया है। विधायक ने पुलिस को मामले में कार्यवाही करने की बात कही है, शहर में इतनी चोरियां हो रही है लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है,अब आम जनता का धीरे धीरे पुलिस के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। जब पुलिस ही आम जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती है जो आम लोग कैसे उन्हें सपोर्ट करेंगे।

अन्य अपराधों के साथ चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करें पुलिस-विवेक पटेल

विधायक विवेक पटेल ने बताया कि यह चिंतनीय है कि एक माह के भीतर तीन बड़ी चोरियां हो गई। चोरी मामले में एफआईआर नहीं करने की जानकारी के बाद हमने एसडीओपी और थाना प्रभारी से मुलाकात कर उन्हें कहा कि पुलिस चोरियों के मामले में कार्यवाही करें। ताकि आरोपी पकडे जाए और लोगों में डर खत्म हो। हमने पुलिस से कहा है कि वह अन्य काम के साथ ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो,शहर में गश्त बडाए ताकि अपराधियों पर पुलिस का डर बना रहे। थाना क्षेत्र में एक माह के भीतर तीन बड़ी चोरी हुई है,जिसके फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने हमे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे।

शासकीय हाई स्कूल लिंगमारा में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का हुआ समापन

पद्मेश न्यूज। डोंगरमाली। शासकीय हाई स्कूल लिंगमारा में १५ जुलाई से २९ जुलाई २०२६ तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा का आयोजन अत्यंत श्रद्धा उत्साह एवं भारतीय संस्कृति की गरिमा के अनुरूप किया गया। पखवाड़े का शुभारंभ प्रथम दिवस १५ जुलाई को विद्यालय की प्रार्थना सभा में प्राचार्य श्री मेरावी एवं समस्त विद्यालयीन स्टाफ की उपस्थिति में माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। पखवाड़े के दौरान निर्धारित कैलेंडर के अनुसार प्रतिदिन विभिन्न रचनात्मक एवं प्रेरणादायी गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। इनमें नवाचार गतिविधियाँ, निबंध लेखन प्रतियोगिता, योगाभ्यास, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, गुरु.शिष्य परंपरा पर संवाद, कैरियर मार्गदर्शन, एक गुरु एक वृक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम पुरस्कार वितरण तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ प्रमुख रहीं। सभी कार्यक्रम विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। समापन समारोह के अवसर पर माँ सरस्वती एवं महर्षि सांदीपनि गुरु की विधिवत पूजा.अर्चना प्राचार्य श्री मेरावी एवं वरिष्ठ शिक्षक ज्ञानेंद्र पटले के द्वारा की गई। इसके पश्चात विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक.शिक्षिकाओं ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गुरु शिष्य परंपरा विषय पर प्रभावशाली भाषण, प्रेरणादायी गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया। शिक्षक ज्ञानेंद्र पटले ने गुरु की महत्ता को समुद्र की अथाह गहराई से जोड़ते हुए कहा कि गुरु का ज्ञान जितना ग्रहण किया जाए, उतना ही जीवन समृद्ध होता है। उन्होंने गुरु.शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए विद्यार्थियों को सदैव गुरुजनों का सम्मान करने की प्रेरणा दी।

खापा-मेहंदीवाड़ा मार्ग पर बाइक सवार २२ वर्षीय युवा गंभीर घायल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा से मेहंदीवाड़ा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। फेरी लगाकर सामान बेचने वाले दो मोटरसाइकिल चालकों की लापरवाही के कारण एक २२ वर्षीय युवा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खापा निवासी २२ वर्षीय संदीप पिता पुनाराम लांजेवार पेशे से किसान हैं। वर्तमान में खेती.किसानी का सीजन चलने के कारण संदीप अपने खेत पर काम करने गया हुआ था। वह खेत का काम निपटाकर खाना खाने के लिए मोटरसाइकिल से अपने घर खापा वापस लौट रहा था तभी मेहंदीवाड़ा की ओर से आ रहे दो

फेरीवाले मोटरसाइकिल चालकों ने उसे ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि संदीप अपनी बाइक से अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर दूर जा गिरा। दुर्घटना में उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें आई हैं। उसके सिर, हाथ और पैरों में गहरी चोट लगी है जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। हादसे के तुरंत बाद मार्ग से गुजर रहे और आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई। ग्रामीणों की मदद से लहूलुहान अवस्था में संदीप को तत्काल वारासिवनी के सिविल अस्पताल लाया गया जहां उसका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में घायल को हाथ पैर सर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में अंदरूनी और बाहरी चोटे आई है।

जनपद पंचायत में बिदाई समारोह का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत भवन के सभा कक्ष में ३१ जुलाई को एक गरिमामय एवं भावुक माहौल में बिदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनपद पंचायत से हाल ही में एवं पूर्व में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से सम्मानपूर्वक विदाई देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माया उइके, उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा अमूले, जनपद सदस्य संदीप राणा, कृष्ण हनवत, पूर्व जनपद अध्यक्ष किशोर अमूले, तहसीलदार एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना कुशराम तथा सहायक यंत्री सरोज सरईया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। इस सामूहिक बिदाई समारोह में इरफान अहमद खान प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी जो ३१ जुलाई को सेवानिवृत्त एवं अशोक कुमार पांडे सहायक लेखा अधिकारी, मदनलाल उइके पंचायत सचिव ३० अप्रैल को सेवानिवृत्त एवं पूर्व में सेवानिवृत्त पंचायत समन्वयक अधिकारी देवेंद्र मिश्रा को उनके उत्कृष्ट सेवाकाल के उपरांत बिदाई दी गई। समारोह के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं सहयोगियों ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कार्यशैली, सौम्य व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा और सहयोगपूर्ण रवैये की जमकर प्रशंसा की। वहीं उनके साथ बिताए गए समय और शासकीय कार्यों के दौरान मिले सहयोग की पुरानी यादों को साझा किया। विदाई ले रहे अधिकारी कर्मचारियों ने अपने संबोधन में समस्त स्टाफ और जनप्रतिनिधियों से मिले स्नेह एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पंचायत में पदस्थ शेष अधिकारी और कर्मचारी भविष्य में भी इसी तरह आपसी सामंजस्य और सहयोग के साथ जनहित के कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर जनपद क्षेत्र के पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत निरीक्षक, सब इंजीनियर सहित जनपद पंचायत का समस्त अमला बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्ज्वल एवं दीर्घायु भविष्य की कामना की गई

नपा परिषद में सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान का हुआ समापन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ राष्ट्र व्यापी अभियान का संचालन किए जाने निर्देश जारी किए गए थे । अभियान का मुख्य उद्देश्य मानसून पूर्व एवं मानसून अवधि में बेहतर स्वच्छता एवं साफ सफाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर जल जनित एवं वेक्टर जनित बीमारियों रोगों की रोकथाम सुनिश्चित करना था। अभियान १६ जून से ३१ जुलाई २०२६ तक संपादित किया जाना था जो निकाय नगर पालिका वारासिवनी द्वारा सतत् रूप से दैनिक गतिविधि कलेंडर तैयार कर स्वच्छता हेतु विभिन्न गतिविधियां संपादित की जाकर ३१ जुलाई २०२६ को समारोह पूर्वक अभियान का समापन किया गया। मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद वारासिवनी के द्वारा संचालित सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का नगर में जनजागरूकता रैली एवं स्वच्छता शपथ के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ स्वच्छता जागरूकता रैली से हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छता मित्रों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। रैली के माध्यम से नगरवासियों को स्वच्छता बनाए रखने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण करने, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फैलाने तथा

जलजनित एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया। रैली उपरांत आयोजित समारोह में सभी उपस्थित जनों को स्वच्छता एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों एवं नगर पालिका के सफाई अमले की सराहना करते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की गई। नपा अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांदरे ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दैनिक दायित्व है। जनसहभागिता से ही हम अपने नगर को स्वच्छए सुंदर एवं रोगमुक्त बना सकते हैं। सभी नागरिक भविष्य में भी स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूर्य प्रकाश ऊके ने कहा कि अभियान के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान, नालियों की सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, डोर.टू.डोर कचरा संग्रहण तथा व्यापक जनजागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं। यह अभियान भले ही औपचारिक रूप से समाप्त हुआ हो, लेकिन नगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में नगर पालिका परिषद के द्वारा सभी नागरिकों से स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने, अपने घर एवं आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने तथा नगर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में निरंतर सहयोग करने की अपील की गई।

खेत से लौटे किसान को अज्ञात जीव ने काटा अस्पताल में उपचार जारी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम पिपरिया में खेत से लौटकर मवेशियों की देखरेख कर रहे एक किसान को अज्ञात जीव के द्वारा काट लेने का मामला सामने आया है। घटना के बाद किसान की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरिया निवासी नन्नू पिता यादो राउत ५५ वर्ष रोज की तरह सुबह अपने खेत गए हुए थे। दिनभर खेती.किसानी का काम करने और मवेशी चराने के बाद वे शाम को वापस अपने घर लौटे। घर पहुँचकर जब वे मवेशियों को बाँधने के बाद उन्हें पैरा डाल रहे थे तभी अचानक किसी अज्ञात जीव ने उन्हें काट लिया। इसके कुछ ही देर बाद किसान की स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने बिना समय गंवाए उन्हें तत्काल स्थानीय सिविल अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों की देखरेख में किसान को भर्ती कर उनका प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में किसान का इलाज जारी है।

सांदीपनि विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का हुआ समापन, टॉपर बच्चों को किया सम्मानित

पद्मेश न्यूज। खैरलांजी/वारासिवनी। खैरलांजी सांदीपनि विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का समापन समारोह उत्सव पर्व आयोजित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र सहारे ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालय में १५ से २९ जुलाई २६ तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया गया ।इसका उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा का संवर्धन साथ ही शिक्षकों के सम्मान विद्यार्थियों में संस्कारों का विकास तथा शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता मानसिंह बहेटवार जिला पंचायत सदस्या खैरलांजी ने किया। विशिष्ट अतिथि बी एल मस्करे सेवा निवृत्त शिक्षक तथा एम के तिवारी बीईओ खैरलांजी एवं पालकगण उपस्थित रहे। बी एल मस्करे ने विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने अधिक सुनकर सीखने की आदत विकसित करने तथा जिला प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत सदस्या ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु

और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र होता है तथा शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बीईओ मुकेश कुमार तिवारी ने गुरु और शिष्य के महत्व को बताते हुए कबीर दास के दोहे से प्रेरणा लेते हुए कहा कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो गुरु की आज्ञा का पालन कर उनके कहे हुए वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। गुरु पूर्णिमा पखवाड़े में समस्त गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रथम तीन छात्रों को विद्यालय परिवार की ओर से उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा ९ वीं से १२ वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपने गीत भाषण गुरु शिष्य रोल प्ले नाटक प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विगत सत्र में कक्षा दसवी में प्रथम आने वाली रमिता राजेंद्र वाघाड़े एवं बारहवी में प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा रुचिता धनेन्द्र लिल्हारे एवं छात्र रूपेश धनुराम नगपुरे को परिजनों के साथ शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती हर्षिता शिवहरे शिक्षिका एवं बीजू बघेले शिक्षक के द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य शैलेन्द्र कुमार सहारे के द्वारा किया गया।

सडक दुर्घटनाओं की चौंकाती हकीकत

भारत में सडक दुर्घटनाओं में कमीं न आना बेहद दुर्भग्यजनक है। कई वर्षो के आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद आशातीत सफलता न मिलनाए कहीं न कहीं सडक पर चलने वालों की मनोदशा पर भी निर्भर करता है। इसी चलते हर रोज कहीं न कहीं से भीषण सडक दुर्घटनाओं के दुखद समाचार मिल ही जाते हैं। भारत सरकार की परिभाषा में एक से ज्यादा लोगों की मौत को भीषण सडक हादसा माना जाता है। सडक हादसों में बेवजह लाखों जान हर वर्ष जाती है।

यदि केवल किसी एक वर्ष के डेटा पर नजर डालें तो काफी चिंताजनक स्थिति है। वर्ष 2023 के आंकड़े ही लें तो दुर्घटनाओं की भयावह तस्वीर उभरती है। इस वर्ष 68783 हिट एण्ड रन मामलों में 31209 मौतें हुई जबकि 54574 लोग घायल हुए। सभी तरह की दुर्घटनाओं का विश्लेषण काफी सोचने और डराने को मजबूर करता है। इसी वर्ष सडक पर खड़े वाहनों से टकराकर 13810 दुर्घटनाओं में 5636 मौतें और 12575 घायल हुए। पीछे से टकराने की दुर्घटनाओं में 36804 मौतें 107161 घायल हुए। साइड से टक्कर की 73805 घटनाओं में 20623 मौतें और 74017 घायल हुए। सड? से नीचे गिरने की 21527 घटनाओं में 10196 लोगों की मृत्यु हुईए 20719 घायल हुए। स्थिर वस्तु से टकराने की 17451 घटनाओं में 8291 मृत्यु और 16416 घायल हुए। जबकि वाहन पलटने की 18905 घटनाओं में 9124 की मृत्यु और 21216 घायल हुए। वहीं आमने.सामने की टक्कर की 84348 दुर्घटनाओं में 28989 की मृत्यु और 89867 घायल हुए। अन्य दुर्घटनाओं में 71298 घटनाओं में 22109 की मृत्यु हुई जबकि घायलों की संख्या 66280 रही। इस तरह केवल 2023 में 480583 दुर्घटनाओं में 172890 मौतें और 462825 दुर्घटना का शिकार हुए जो अन्य क्षति छोडकर मानवीय हैं।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ज्यादातर दुर्घटनाएँ तेज गतिए बिना हेलमेट वाहनों के बीच बिना सुरक्षित दूरी सुस्ती नींद के झोंके वाहन चलाते समय धूम्रपान शराब या किसी अन्य नशे में होने से दुर्घटनाएँ होती हैं। रात में हमारे वाहन के हेडलाइट्स टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स खराब होने या काम नहीं करने टायरों पर ध्यान नहीं देने और ज्यादा पुराने घिसे कटे.फटे क्रैक्स से भरपूर टायरों का उपयोग बरसात के मौसम में घिसे टायरों पर ट्रैक्शन कम होने से वाहन फिसलने और प्राय: ब्रेक नहीं लगने से भी दुर्घटनाएं आम हैं। ब्रेक की नियमित जांच से कई तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें भी ध्यान भटकाता है। गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में आगे निकलने की होड़ और ओवर टेक भी वजह है। छोटी सडकों पर ध्यान नहीं देना कि कहीं सामने दूसरा वाहन तो नहीं आ रहा जबकि हाइवे पर इंडीकेटर का सही उपोयग नहीं करना दुर्घटनाओं का सबब बनता है। ओवरटेक की होड़ से भी दुर्घटनाएँ होती हैं। यह सभी वो छोटे.छोटे उपाय व यातायात के नियम हैं जिन्हें हम जानते तो हैं पर अमल में नहीं लाते हैं। थोड़ी सतर्कता थोड़ी सजगता से बड़ी.बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसीलिए यातायात विभाग का बेहद लोकप्रिय नारा है दुर्घटना से देर भली।

जंतर-मंतर छात्र आंदोलन में बल प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, से उभरती नई संवैधानिक बहस

वैश्विक स्तरपर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल चुनावों से नहीं,बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि राज्य असहमति,विरोध और सार्वजनिक आंदोलनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। अब छात्र आंदोलन पर बल प्रयोग का प्रश्न केवल पुलिस कार्रवाई या कानून- व्यवस्था तक सीमित विषय नहीं रह गया है।यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, राज्य की सुरक्षा- जम्मिेदारी,बल प्रयोग की वैधानिकता,कमांड की जवाबदेही और न्यायिक निगरानी इन पांचों के बीच संतुलन का गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर क्षेत्र में हुए छात्र प्रदर्शन और उसके दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा कथित रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में 30 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों ने इस बहस को राष्ट्रीय ही नहीं,बल्कि अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना दिया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि भीड़ नियंत्रण के नाम पर किसी भी विशेष प्रकार के बल का उपयोग सामान्य प्रशासनिक सुविधा का साधन नहीं हो सकता। बल प्रयोग की वैधानिकता केवल इस आधार पर निर्धारित नहीं होतीकि स्थिति तनावपूर्ण थी, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वास्तविक खतरा कितना गंभीर था,क्या कम-हानिकारक विकल्प उपलब्ध थे,क्या कार्रवाई आवश्यक और अनुपातिक थी तथा क्या पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानून और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप हुई। साथियों, 30 जुलाई 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि पुलिस को केवल अत्यंत गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में ही पैलेट गन के उपयोग का अधिकार हो सकता है।यह टिप्पणी ग्रेडेड रिस्पांस अर्थात परिस्थितियों की गंभीरता के अनुसार क्रमिक और नियंत्रित प्रतिक्रिया के सिद्धांत को रेखांकित करती है। इसका अर्थ यह है कि भीड़ नियंत्रण में हर परिस्थिति के लिए एक ही प्रकार की शक्ति का प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध, सभा और अभिव्यक्ति नागरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दूसरी ओर, राज्य पर सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने, हिंसा रोकने,नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने और सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी है।इन दोनों दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना प्रशासन की सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक है।यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो उसे केवलअसहमति या राजनीतिक आलोचना के कारण बलपूर्वक समाप्त करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।लेकिन यदि किसी प्रदर्शन में गंभीर हिंसा आगजनी जानलेवा हमला या व्यापक सार्वजनिक खतरा उत्पन्न हो,तो राज्य निष्क्रिय भी नहीं रह सकता। इसलिए मूल प्रश्न बल प्रयोग होना चाहिए या नहीं का नहीं, बल्कि कब, क्यों, किस अधिकार के अंतर्गत, किस सीमा तक और किस जवाबदेही के साथ बल प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित लॉग बुक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश इस पूरे प्रकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलू है।यह आदेश किसी जवान, अधिकारी या संस्था को दोषी घोषित नहीं करता। न्यायालय ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहलेआवश्यक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर बल दिया है। कानून के शासन में निष्पक्ष जांच का पहला आधार यही है कि तथ्य नष्ट न हों, रिकॉर्ड में परिवर्तन न हो और भविष्य की न्यायिक या स्वतंत्र जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रहें।अम्युनिशन लॉग से यह समझने में सहायता मिल सकती है कि संबंधित इकाई को कितना गोला-बारूद जारी किया गया,कितना उपयोग हुआ,किस प्रकार के उपकरण या कारतूस उपलब्ध थे, किस समय किस स्तर पर उनका उपयोग दर्ज किया गया और कार्रवाई की प्रशासनिक श्रृंखला क्या थी। यह रिकॉर्ड घटनाक्रम को केवल आरोपों या प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर समझने का अवसर देता है। साथियों रिकॉर्ड संरक्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी विवादित बल-प्रयोग की घटना में अक्सर दो विपरीत कथाएं सामने आती हैं।एक पक्ष यह कह सकता है कि कार्रवाई अनावश्यक या अत्यधिक थी,जबकि दूसरा पक्ष यह तर्क दे सकता है कि सुरक्षा बलों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा और उन्होंने कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता केवल किसी एक पक्ष की बात स्वीकार करने से नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों की जांच से स्थापित होती है।यदि डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो, वायरलेस संचार, ड्यूटी चार्ट, आदेश-पत्र, अम्युनिशन लॉग और अन्य दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि बल प्रयोग वास्तविक खतरे के अनुपात में, वैध आदेश के अंतर्गत और निर्धारित एसओपी के अनुसार हुआ, तो वही रिकॉर्ड सुरक्षा बलों की पेशेवर विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है। इसके विपरीत, यदि रिकॉर्ड और वास्तविक घटनाक्रम में असंगति मिलती है, तो जवाबदेही तय करने का आधार तैयार हो सकता है। इसलिए अम्युनिशन लॉग सुरक्षित रखने का अर्थ केवल संभावित जांच नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से संरक्षित करना है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ सुरक्षा बलों के लिए भी सटीकता से एक संस्थागत सुरक्षा-कवच हो सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पैलेट गन के छर्रे लगने से घायल नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के सर्वोत्तम तथा उचित उपचार को सुनिश्चित करने का निर्देश देकर राज्य की मानवीय जिम्मेदारी को भी केंद्र में रखा। किसी भी भीड़-नियंत्रण कार्रवाई के बाद प्रशासन का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बहाल होने तक समाप्त नहीं हो जाता। यदि किसी नागरिक को चोट लगी है,तो उसे समय पर चिकित्सा सहायता,विशेषज्ञ उपचार, आवश्यक जांच और पुनर्वास उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से आंख, चेहरे या शरीर के संवेदनशील हिस्सों में लगी चोटें दीर्घकालिक या स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए चिकित्सा सहायता को केवल राहत या सहानुभूति के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रशासन की जवाबदेही के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में भी यह सिद्धांत स्वीकार किया जाता है कि कानून-प्रवर्तन की कार्रवाई के बाद घायल व्यक्तियों को यथाशीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस दृष्टि से न्यायालय का निर्देश केवल उपचार संबंधी आदेश नहीं, बल्कि राज्य के कर्तव्य-आधारित मानवीय दायित्व का पुनर्स्मरण है। साथियों, इस मामले में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी तथा अन्य पीड़ितों द्वारा दाखिल याचिका में नागरिक प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग किए जाने से बहस का एक महत्वपूर्ण आयाम सामने आया याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कथित रूप से धातुयुक्त पैलेट के उपयोग पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि ऐसे पैलेट शरीर के भीतर गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तर्क के पीछे मुख्य चिंता यह है कि किसी भी भीड़-नियंत्रण उपकरण को केवल उसके नाम या घोषित उद्देश्य के आधार पर कम घातक मान लेना पर्याप्त नहीं है। किसी उपकरण के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके तकनीकी स्वरूप,उपयोग की दूरी,लक्ष्य, परिस्थितियों, प्रशिक्षण और इस्तेमाल की पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए। कोई उपकरण अपेक्षाकृत कम घातक हो सकता है, लेकिन उसका गलत, अत्यधिक या अनियंत्रित प्रयोग गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। इसलिए उपकरण की प्रकृति के साथ-साथ उसके प्रयोग का तरीका भी कानूनी और नैतिक समीक्षा का विषय होना चाहिए। साथियों, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को पूर्ण प्रतिबंध की मांग के बजाय स्पष्ट और कठोर प्रोटोकॉल अथवा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के अनुरोध पर विचार करने की सलाह देना एक व्यावहारिक और संतुलित न्यायिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है।

किसी उपकरण पर पूर्ण प्रतिबंध और उसके अनियंत्रित उपयोग के बीच एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है कठोर नियमन,सीमित उपयोग, स्पष्ट अनुमति-प्रक्रिया, अनिवार्य रिकॉर्डिंग, स्वतंत्र समीक्षा और जवाबदेही। न्यायालय द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की एडवाइजरी का संदर्भ इस बात की ओर संकेत करता है कि भीड़-नियंत्रण के लिए स्पष्ट मानक, प्रशिक्षित कमांड संरचना और दस्तावेजी प्रक्रिया आवश्यक हैं। यदि किसी विशेष उपकरण का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि असाधारण परिस्थिति की परिभाषा क्या होगी, खतरे का आकलन कौन करेगा, अनुमति किस स्तर से मिलेगी, क्या पहले चेतावनी दी जाएगी, क्या कम-हानिकारक विकल्पों का उपयोग किया जाएगा और कार्रवाई के बाद समीक्षा किस प्रकार होगी।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आवाज बनते मोहन

-हर्षवर्धन पान्डे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालने के बाद से किसानों को प्राथमिकता देते हुए राज्य में किसान हितैषी मुख्यमंत्री की एक नई छवि गढ़ रहे हैं। वे न केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित हैं, बल्कि खुद खेतों में उतरकर किसानों के साथ जुड़कर उनकी आय बढ़ाने के ठोस कदम उठाने के साथ ही किसान कल्याण वर्ष 2026 में और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सतत रूप से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित कर उन्होंने अपने इस संकल्प को और मजबूती प्रदान की है।मोहन सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बलराम कृषि महोत्सव 15 जुलाई 2026 को इंदौर से शुरु हुआ है जिसके तहत 13 नवंबर 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में बड़े आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में ब सीधे राशि पहुंचाना मध्यप्रदेश में मोहन सरकार की एक प्रमुख पहचान बन गया है। जुलाई 2026 में खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में उन्होंने सिंगल क्लिक से 82.70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। किसानों को 2025-26 की तीसरी और 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपये मिले। इससे पहले भी पीएम-किसान और राज्य योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं।सरकार ने लगभग 10,500 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख किसान हितैषी योजनाओं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन समेत अन्य को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। पहली कृषि कैबिनेट में 27,000 करोड़ रुपये से अधिक के रोडमैप को मंजूरी दी गई, जिसमें सिंचाई, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया गया।सोयाबीन के बाद सरसों को भावांतर योजना में शामिल किया गया। उड़द पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान हुआ। धान उत्पादकों के लिए भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की गई। कोदो-कुटकी जैसी श्रीअन्न फसलों पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और सरकारी खरीद अभियान शुरू किया गया। गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यह सभी बड़े कदम किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाते हुए किसानों को एक सुनिश्चित आय का आधार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान कल्याण को अपना बड़ा विजन बनाया। डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने और आगे 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध जैसी बड़ी परियोजनाओं से लाखों किसानों को लाभ प्रदान करने की दिशा में अपने कार्यकाल में उन्होनें एक नई लकीर खींचने का काम किया है। अगले तीन वर्षों में 30 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य बनाया है जिससे प्रदेश के किसान ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेंगे। आज प्रदेश में उनके कार्यकाल में कृषक मित्र योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप दिए जा रहे हैं। इसी तरह माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान जारी रखा गया है। मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में देश में अग्रणी राज्य है जहाँ 16 लाख हेक्टेयर से अधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र है और सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि यंत्रीकरण के लिए 2,868 करोड़ रुपये का प्रावधान और देश में सर्वाधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के साथ खेत में उतरकर खुद धान की रोपाई करने में भी पीछे नहीं रहे। बलराम कृषि महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में वह किसानों से सीधा संवाद करते देखे जा सकते हैं। उनके दूरदर्शी विजन में 17 विभागों को मिलाकर खेती, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण पर्यटन पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा, उर्वरक की उपलब्धता पर एसएमएस अलर्ट, ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल जैसी सुविधाओं ने आज मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मध्यप्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर पिछले दो दिनों से किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। किसानों ने एमएसपी पर खरीद, ई-टोकन सिस्टम खत्म करने और खाद की उपलब्धता जैसी मांगों पर भोपाल कूच किया। 19 संगठनों के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नर्मदापुरम से मार्च करते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए सीएम आवास के से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। इससे सड़कों पर जाम और तनाव की स्थिति बन गई थी।मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने किसानों के बड़े आंदोलन को देखते हुए तत्काल मंत्रियों की एक समिति गठित की। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना समेत अन्य मंत्रियों ने किसानों से बात की और मंत्रालय में मोर्चा संभाला। मंत्रालय से लेकर पुलिस और प्रशासन को सक्रिय किया। सरकार ने मूंग खरीद की सीमा 25त्न से बढ़ाकर 60त्न करने का बड़ा एलान कर किसानों का दिल जीत लिया। खरीद समय-सीमा बढ़ाने के बड़े एलान के साथ ही खाद वितरण का ई-टोकन सिस्टम स्थगित कर समीक्षा के लिए समिति बनाई गई। इसके बाद अधिकांश किसान संगठनों ने आंदोलन वापस ले लिया और सड़कें खुल गई। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। सरकार द्वारा यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया। यह समिति ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई-टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने ठोस निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। वह केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहते। वह अपनी सभी योजनाओं को मिशन मोड में लागू कर रहे हैं और किसानों से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं। यही नहीं केंद्र की सभी योजनाओं को प्रदेश स्तर पर मजबूती से लागू कर रहे हैं।आज दलहन, तिलहन, मक्का और टमाटर उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना गया है। सोलर ऊर्जा, मूल्य समर्थन, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के संयोजन से वे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में सभी अन्नदाता बंधुओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।किसान हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव की यह नई छवि भविष्य में मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आज उनके सफल प्रयासों से न केवल प्रदेश के किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि खेती को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने का नया कार्य भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बेहतर संवाद से किसान संगठनों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाकर सही मायनों में अपनी बेहतर राजनीतिक परिपक्वता को दिखाने का कार्य किया है।

इस्तीफा तो हो गया लेकिन क्या छात्रों को न्याय मिला?

कई दिनों के धरना-प्रदर्शन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहली नजर में इसे आंदोलन की बड़ी जीत और लोकतंत्र की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वही है, जो हर छात्र और अभिभावक के मन में है—क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो गया? क्या इससे पेपर लीक की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लौट आएगी? क्या लाखों विद्यार्थियों की मेहनत अब बिना किसी भय के रंग लाएगी? इन सभी सवालों का उत्तर फिलहाल नकारात्मक दिखाई देता है। यही कारण है कि आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन केवल एक मंत्री के इस्तीफे से नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में आने वाले वास्तविक सुधारों से किया जाना चाहिए। सबसे पहले उस बात का उल्लेख आवश्यक है जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अभिजीत दीपके ने मंच से कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने इसे अपनी और लोकतंत्र की जीत बताया। निस्संदेह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है और यदि सरकार ने छात्रों के दबाव के बाद निर्णय लिया है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत माना जा सकता है। लेकिन यहां यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दीपके की राजनीतिक या आंदोलनकारी जीत अपनी जगह हो सकती है, परंतु उस छात्र को इससे क्या मिला जिसकी एक वर्ष की मेहनत पेपर लीक के कारण बर्बाद हो गई? जो विद्यार्थी मानसिक तनाव में आ गया, जिसने दोबारा परीक्षा दी, जिसने आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों का सामना किया, उसके जीवन में अभी तक कोई ठोस परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसलिए केवल सुर्खियों में आने या आंदोलन की सफलता का दावा करने से छात्रों की वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं हो जातीं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद जारी पत्र में कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी और उनका उद्देश्य किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देना था। उन्होंने यह भी कहा कि देश की युवा शक्ति उनके लिए सर्वोपरि है और राष्ट्रहित तथा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पद छोड़ा। यह एक जिम्मेदार राजनीतिक संदेश है। इसी तरह सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, मुकदमे वापस लेने की बात कही, पीड़ित छात्रों के लिए मुआवजे की घोषणा की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर चर्चा का भरोसा दिया। हिंसा और तनाव के बावजूद सरकार ने अंतत: संवाद का रास्ता चुना। यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक माना जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि किसी मंत्री का इस्तीफा स्वयं में समाधान नहीं होता। पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे तंत्र की कमजोरी का परिणाम होती हैं। यदि व्यवस्था में खामियां बनी रहेंगी तो नया मंत्री भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करेगा। छात्रों को मंत्री बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने से लाभ मिलेगा। आज देश के करोड़ों विद्यार्थी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अब पेपर लीक पूरी तरह बंद हो जाएगा? दुर्भाग्य से इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं और संगठित नकल गिरोहों के सक्रिय होने की घटनाएं सामने आई हैं। इसका अर्थ है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुका है। ऐसे नेटवर्क में छोटे-छोटे एजेंटों से लेकर आर्थिक लाभ उठाने वाले बड़े मास्टरमाइंड तक शामिल होते हैं। कार्रवाई अक्सर निचले स्तर तक सीमित रह जाती है जबकि पूरे षड्यंत्र को संचालित करने वाले लोग बच निकलते हैं। जब तक इन मास्टरमाइंड तक कानून की पहुंच नहीं होगी, तब तक छात्रों का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो सकता। सरकार ने पेपर लीक से जुड़े अपराधों के लिए दस वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। कठोर कानून अपराधियों के मन में भय पैदा कर सकते हैं। लेकिन केवल कानून बना देने से न्याय नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब अपराध की निष्पक्ष जांच हो, असली दोषियों की पहचान हो और समयबद्ध तरीके से उन्हें सजा मिले। यदि जांच केवल छोटे आरोपियों तक सीमित रह गई तो कठोर कानून भी अपनी प्रभावशीलता खो देंगे। यही कारण है कि जांच एजेंसियों को केवल गिरफ्तारियां करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे नेटवर्क की आर्थिक, डिजिटल और तकनीकी जांच करनी चाहिए। जिन लोगों पर गंभीर आरोप हों, उनके बैंक खातों, संपत्तियों, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल लेन-देन और आपराधिक नेटवर्क की गहन पड़ताल होनी चाहिए। वैज्ञानिक जांच की उपलब्ध कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग भी आवश्यक परिस्थितियों में किया जा सकता है, ताकि वास्तविक साजिशकर्ताओं तक पहुंचना संभव हो। उद्देश्य केवल गिरफ्तारियां दिखाना नहीं बल्कि पूरे माफिया तंत्र को समाप्त करना होना चाहिए। इस पूरे विवाद में कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है। यह सत्य है कि देश के अधिकांश कोचिंग संस्थान ईमानदारी से छात्रों को शिक्षा देते हैं, लेकिन यदि कोई संस्था पेपर लीक या परीक्षा माफिया से जुड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। उसकी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए, उसकी वित्तीय गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और यदि अपराध सिद्ध हो तो उसे शिक्षा क्षेत्र से स्थायी रूप से बाहर किया जाना चाहिए। शिक्षा विश्वास का क्षेत्र है, इसे अवैध कमाई का माध्यम बनाने वालों के प्रति कठोरता आवश्यक है। कई लोग ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या यूएपीए जैसे कठोर कानून लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। इन कानूनों का प्रयोग अपने-अपने कानूनी दायरे में ही किया जा सकता है और उनका उपयोग तथ्यों तथा कानून के अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोई संगठित गिरोह करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके विरुद्ध उपलब्ध सभी प्रभावी कानूनी प्रावधानों का कठोरता से उपयोग होना चाहिए। परीक्षा माफिया को सामान्य आर्थिक अपराधी मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। इससे मुकदमों के शीघ्र निपटारे की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि जांच कमजोर होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सीमित साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देगा। इसलिए तेज अदालतों के साथ मजबूत जांच व्यवस्था और आधुनिक फोरेंसिक तंत्र भी उतना ही आवश्यक है। न्याय केवल जल्दी नहीं बल्कि सही भी होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच छात्रों के मन में एक और उम्मीद है कि क्या भविष्य में वर्ष में दो बार नीट परीक्षा आयोजित होगी। यदि ऐसा होता है तो एक परीक्षा खराब होने पर विद्यार्थियों का पूरा वर्ष बर्बाद नहीं होगा। यह सुधार निश्चित रूप से छात्रों के हित में माना जा सकता है। लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी हो। यदि वर्ष में दो बार परीक्षा होगी लेकिन दोनों बार पेपर लीक का खतरा रहेगा तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

आज आवश्यकता शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया, सुरक्षित मुद्रण, डिजिटल एन्क्रिप्शन, परिवहन व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया—इन सभी क्षेत्रों में एक साथ सुधार करना होगा। केवल मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता तीनों की आवश्यकता होती है। इस पूरे आंदोलन से सरकार को भी एक महत्वपूर्ण संदेश मिला है कि आज का युवा केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कहा कि आज की पीढ़ी हर बात का कारण जानना चाहती है और सरकार को युवाओं से संवाद करना चाहिए। यह सलाह केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए भी प्रासंगिक है। विद्यार्थियों का विश्वास तभी लौटेगा जब उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत किसी माफिया या भ्रष्ट तंत्र की भेंट नहीं चढ़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम समाधान मान लेना भूल होगी। छात्रों की वास्तविक जीत उस दिन होगी जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं होगा, किसी अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, किसी परिवार का सपना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा और किसी विद्यार्थी को यह डर नहीं रहेगा कि उसकी मेहनत से अधिक कीमत किसी माफिया की पहुंच की है। इसलिए आज आवश्यकता किसी व्यक्ति के परिवर्तन की नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की है। तभी कहा जा सकेगा कि इस संघर्ष का सबसे बड़ा विजेता कोई नेता या आंदोलनकारी नहीं, बल्कि देश का मेहनती विद्यार्थी बना।

-कांतिलाल मांडोत

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। ताजा लेवाली के चलते शुक्रवार को अनाज मंडी में चना बाजार उछाल पर रहे। तुअर व उड़द में भाव बने रहे। खाद्य तेलों में मजबूती बनी। तिलहनों में सोयाबीन बना रहा। किराना जिंसों में सूखे मेवों में भाव मजबूती पर रहे। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार चने में तेजी मंदी के समीकरण बने हुए है। शुक्रवार को ताजा लेवाली से भावों में उछाल रहा। चना बढ़िया मालों में 6550-6650 रू. प्रति क्विंटल बोला गया। तुअर व उड़द में मजबूती रही। खाद्य तेलों में पूछपरख आने से भावों में सुधार बना। तिलहनों में सोयाबीन बाजार टिके रहे। उधर, किराना जिंसों में सूखे मेवों में पूछपरख से भावों में मजबूती रही। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4730-4800, खोपरा गोला 375-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडि?यम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडि?यम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 3000-3050, (160) 3400, (200) 3600-3650, (250) 4200-4250,

तेल- सींगदाना 1720-1740, मुम्बई 1750, राजकोट तेलिया 2700, सोया साल्वेंट 1400-1405, सोया रिफाइंड 1455-1460, कपास्या 1590-1600, धूलिया 1600, कड़ी 1610,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1700, मुम्बई पाम 1480, मुम्बई सोया 1490,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2690, देवास-उज्जैन 2690, खंडवा-बुरहानपुर 2660, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8100-8300, रायडा 7100-7200, सोयाबीन 7000, टोली (महुआ बीज) 5300-5400, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6550-6650, एवरेज 6200-6300, विशाल 6350-6450, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000-6050, एवरेज 5800-5900, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7200, मूंग पुराना बोल्ड 7400-7500, मीडियम 7000-7300, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9300-9500, उड़द गर्मी 8600-9300, ग्रेविटी क्लीन 9700-10000, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजार व्यापार सामान्य ही रहा। विदेशी बाजारों की मजबूती से दोनों मूल्यवान धातुओं में बाजार तेजी के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चॉंदी (9999) 220500, चॉंदी (99) 220400, टंच 219800, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 141850,

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया एक पैसे की तेजी के साथ ही 95.49 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में रुपया 20 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.30 पर बंद हुअ। विदेशी पूंजी प्रवाह और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी रुपये को बल मिला। घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने से रुपये की तेजी सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.40 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में बढ़त के साथ 95.30 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे की मजबूती दिखाता है। रुपया लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज करते हुए गुरुवार को 26 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.50 पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ

सेंसेक्स 166, निफ्टी 66 अंक ऊपर आया

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही लिवाली हावी रहने से आई है। आज ऑटोमोबाइल और मीडिया शेयरों में सबसे अधिक उछाल आया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 166.49 अंकों की तेजी के साथ ही 78,094.64 के स्तर पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 66.45 अंकों की बढ़त के साथ ही 24,383.60 के स्तर पर बंद हुआ है। आज कारोबार में सेंसेक्स के 30 में से ज्यादातर शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आकर बंद हुए। वहीं बजाज फाइनेंस , एमएम आडानी पोर्ट और टाटा स्टील के शेयरों में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर टीसीएस, इंफोसिस और टेक महिन्द्रा के शेयर गिरे हैं। आज मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। इससे निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.51 फीसदी तक ऊपर आया जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई। आज ज्यादातर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए

हैं। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी मीडिया में रही और यह 2 फीसदी से ज्यादा उछल गया। निफ्टी ऑटो और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी 1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त रही। इसके अलावा निफ्टी मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे इंडेक्स भी लाभ के साथ बंद हुए। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी करीब 1.70 फीसदी तक गिर गया। वहीं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में भी 1 फीसदी से ज्यादा की कमजोरी रही। जानकारों के अनुसार बाजार में आई तेजी के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीददारी से भी बाजार उछला है। इसके अलावा रुपये में आई मजबूती और दिग्गज कंपनियों के अच्छे परिणामों से भी बाजार को बल मिला। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की अच्छी शुरुआत रही। वित्तीय सेवा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार ऊपर आया। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 43.30 अंक की बढ़त के साथ 77,971.45 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 भी 33.55 अंक चढ़कर 24,350.70 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

एनटीपीसी की हरित क्रांति- निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने कोयले को पछाड़ा

नई दिल्ली। एजेंसी। भारत की सबसे बड़ी ताप बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। कंपनी पहली बार कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाएं विकसित कर रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 16.4 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो निर्माणाधीन कोयला-आधारित परियोजनाओं की 15.7 गीगावाट क्षमता से अधिक है। यह देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, जहां पारंपरिक रूप से ताप बिजली पर एकाधिकार रखने वाली कंपनी अब हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि जून 2026 के अंत तक एनटीपीसी की निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 16.4 गीगावाट हो गई, जो निर्माणाधीन कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं की 15.7 गीगावाट क्षमता से अधिक है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2025 में कोयला आधारित क्षमता 17.3 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर थी, जिसमें अब गिरावट आई है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता जून 2025 से 24 फीसदी बढ़कर 16.4 गीगावाट हो गई है। कंपनी कुल मिलाकर 35.7 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता विकसित कर रही है, जिसमें पनबिजली भी शामिल है। कंपनी ने एक दशक पहले ही अपने नाम से थर्मल पावर हटाकर एनटीपीसी कर दिया था, जो इसके हरित ऊर्जा पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। वर्तमान में एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 91 गीगावाट है, जिसमें 74 गीगावाट ताप बिजली, 12 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 4 गीगावाट पनबिजली शामिल है।

कैपिटल ग्रुप ने आईआईएफएल फाइनेंस में किया 374 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। एजेंसी। अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी कैपिटल ग्रुप ने आईआईएफएल फाइनेंस में एक बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने खुले बाजार सौदों के माध्यम से 374 करोड़ रुपये में 1.49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, जिसे फेयरफैक्स इंडिया की सहयोगी इकाई ने बेचा है। एनएसई आंकड़ों के मुताबिक कैपिटल ग्रुप ने अपनी दो इकाइयों कैप वर्ल्ड फंड इंक और अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस सीरीज ग्लोबल स्मॉल कैपिटलाइजेशन फंड के जरिये आईआईएफएल फाइनेंस के कुल 63,39,355 शेयर औसतन 590 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। वहीं फेयरफैक्स इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स ने भी इतनी ही संख्या में शेयर बेचे। इस लेनदेन के बाद आईआईएफएल फाइनेंस में एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स की हिस्सेदारी 15.18 प्रतिशत से घटकर 13.69 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, हिस्सेदारी बेचने के बाद भी, यह इकाई मुंबई स्थित इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयरधारक बनी हुई है।

आज का राशिफल

मेष- आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। आपके सम्मान और मान में बढ़ोतरी होगी, जिससे मन में गर्व और संतोष महसूस होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से आपकी छवि और निखरेगी। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान-पुण्य में लगाने के लिए सोचेंगे। भाई-बहनों के साथ बेवजह विवाद से बचें, और प्रॉपर्टी संबंधी किसी निर्णय में जल्दबाजी न करें। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है।

वृषभ- आज आप अपने नेतृत्व कौशल और समय प्रबंधन में निखार महसूस करेंगे। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने-फिरने का आनंद भी मिलेगा। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें और किसी पुराने बिजनेस या निवेश संबंधी समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव से माहौल खुशनुमा रहेगा।

मिथुन- आज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित लाभ और खुशियों से भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ाने से रिश्तों की परेशानियां दूर होंगी। नया वाहन खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। धन उधार देने में सावधानी बरतें, क्योंकि वापस मिलने की संभावना कम है। राजनीतिक या सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लेने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कर्क- आज का दिन मिश्रित अनुभव लेकर आएगा, लेकिन फलदायक साबित होगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन आपको अपने काम समय पर पूरा करने में मदद करेगा। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी विरोधी से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने से मन को बड़ी खुशी मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें।

सिंह- आज का दिन सामान्य से बेहतर रहने वाला है। बेवजह विवादों से दूर रहें। नौकरी में कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं और जिम्मेदारियों में जूनियर्स से सहयोग मिलेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। शौक और मनोरंजन पर आप खर्च करेंगे, जिससे खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन मन को संतोष मिलेगा।

कन्या- आज का दिन आपके लिए अनुकूल और सुखद रहेगा। आपकी ऊर्जा और अनुभव आपके काम में लाभ देंगे। संतान से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अपनी वाणी और व्यवहार में सभ्यता बनाए रखें। संतान को पढ़ाई-लिखाई के लिए बाहर भेजने के अवसर बन सकते हैं। धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में भाग लेने से मानसिक संतोष मिलेगा।

तुला- आज आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। घर के रिनोवेशन या छोटे निर्माण कार्य की शुरुआत हो सकती है। माताजी से किसी जरूरी काम को लेकर संवाद होगा। कुछ पुराने शत्रु मित्र बन सकते हैं, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी।

वृश्चिक- आज आपका रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में समय से काम पूरा करने की कोशिश सफल होगी। साथी की समस्याओं का समाधान निकालेंगे और परिवार में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन से सब व्यस्त रहेंगे। छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज-मस्ती में बीतेगा। अगर आपका बिजनेस या धन डूबा हुआ था, तो उसे वापस पाने की संभावना है।

धनु- आज का दिन आपके लिए लाभदायक और उत्साहवर्धक रहेगा। धर्म-कर्म के कामों में रुचि रहेगी। संतान की परीक्षा या कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मौज-मस्ती में समय बिताएंगे और मेहनत का फल भी प्राप्त करेंगे। जरूरी जानकारी साझा करने में सतर्क रहें। पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। बॉस से प्रमोशन को लेकर बातचीत हो सकती है।

मकर- आज आपको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा। सोच-समझकर कदम उठाने से काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो वह वापस मांग सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वाहन चलाने या किसी सहयोगी से मदद लेने में सतर्क रहें। नई कोशिशें सफल होंगी।

कुंभ- आज जोखिम भरे कामों से दूर रहें। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कारोबार में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। किसी सहयोगी से अनावश्यक कहासुनी हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव से माहौल खुशनुमा रहेगा।

मीन- आज का दिन सोच-समझकर काम करने का रहेगा। संतान के करियर को लेकर चिंता हो सकती है। बिजनेस में जोखिम से बचें और अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें। माता-पिता की सेहत पर ध्यान दें। परिवार के साथ मौज-मस्ती और घूमने-फिरने का समय अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

शब्दजाल - 8337

शब्दजाल में 'जैकी श्राफ' अभिनीत 10 फिल्मों के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे व तिरछे हैं.

मिशन कश्मीर, रिफ्यूजी, कोहराम, गंगा की कसम, त्रिदेव, फूल और आग, यमराज, बार्डर, अग्निसाक्षी, परिंदा

गं	रा	जें	द्र	कु	मा	य	वा	ज	पे	यी
द	गा	ल	प्रे	व	जी	म	द	ह	कां	रा
वि	स	की	म	को	ह	रा	म	ल	ख	म
मि	स	स	क	दि	वा	ज	ध	त्रि	श	दु
श	आ	र	ग	स	ज	ना	तू	दे	झ	प
न	ल	ला	र	दि	म	उ	ती	व	घ	रिं
क	व	रि	फ्यू	जी	प	बा	ज	ती	व	दा
श	एं	वा	ई	द	ब	ई	डू	ए	श	न्हा
मी	ड	ल	फू	ल	औ	र	आ	ग	शी	आ
र	गॉ	ल	प	लि	जी	शी	ला	कौ	ल	द
वि	ज	अ	ग्नि	सा	क्षी	डि	त	ब	प	म

शब्दजाल - 8336 का हल

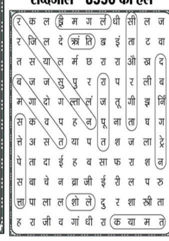

फिल्म वर्ग पहेली- 7281

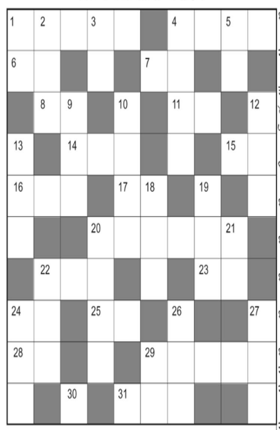

बायें से दायें:-

१. अमिताभ, जया की 'ये जुल्फ कैसी है' गीत वाली फिल्म-२,१,२
४. 'सीमायें बुलाये तुझे' गीत वाली जे.पी.दत्ता की युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक मल्टीस्टारर फिल्म-२,१,१
६. फिल्म 'साया' में नायिका कौन थी-२
७. 'झमका चाँदी दा' गीत वाली मनोज, अरशद, तब्बू, शीबा की फिल्म-२
८. अभिषेक, अंतरा माली की 'बेरंग जिंदगी' गीत वाली फिल्म-२
११. फिल्म 'जीवनमृत्यु' में नायिका थी-२
१४. 'तुम तो परदेसी हो' गीत वाली फराजखान, रानी मुखर्जी की फिल्म-३
१५. अमिताभ, अजय, अक्षय, ऐश्वर्या की 'दिल डूबा' गीत वाली फिल्म-२
१६. 'आज मदहोश हुआ जाये' गीत वाली शशिकपूर, राखी की फिल्म-३
१७. संजय कपूर, रवीना, अदिति की 'हंसता है रूलता' गीत वाली फिल्म-२
२०. 'सनन सनन साय साय हो' गीत वाली गोविंदा, रमैया की फिल्म-४,२
२२. सनी देओल, अमीषा पटेल की 'घर आजा परदेसी' गीत वाली फिल्म-३
२३. 'तू कल चला' गीत वाली संजयदत्त, कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों की फिल्म-२
२४. जैकी, सुनील शेट्टी, डिनो, करिश्मा की 'ऐ सुबह तू' गीत वाली फिल्म-२
२५. 'हुस्ने जाना इधर आ' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-२
२८. देवआनंद, गीता बाली की 'चांदनी रातें प्यार की' गीत वाली फिल्म-२
२९. 'जिनके पास हाथी घोड़ा' गीत वाली राजकुमार, लीना की फिल्म-२,१,२
३०. जीतेंद्र, जयाप्रदा की 'आईने के सौ टुकड़े' गीत वाली फिल्म-१
३१. 'लड़की जो आए बाजार में' गीत वाली जैकी श्रॉफ, मनीषा की फिल्म-३

ऊपर से नीचे:-

१. 'नदिया किनारे आआ' गीत वाली संजय दत्त, आफताब, नंदिता की फिल्म-२
२. ऋषिकपूर, माधुरी दीक्षित की 'जाने वो कैसा चोर था' गीत वाली फिल्म-३
३. 'आजकल पाँव जमीं पर' गीत वाली फिल्म-२
४. अक्षय, करीना कपूर, प्रियंका की फिल्म-४
५. 'दिल दिया है तुझे' गीत वाली अतीन भल्ला, संदली सिन्हा की फिल्म-२
९. राहुल बोस, करीना कपूर की 'जाने क्यूं हमको' गीत वाली फिल्म-३
१०. राजकपूर, परवीन की 'आपसा कोई हसीन' गीत वाली फिल्म-२,२
१२. 'तोता मैना की कहानी' गीत वाली शशिकपूर, शबाना की फिल्म-३
१३. मिलिंद सोमण, किरण झवेर की 'जीना है तेरी' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'सुलगे हुए हैं' गीत वाली जिमी, इरफान, ऋषिता, नम्रता की फिल्म-३
१९. फिल्म 'अवतार' में राजेश की नायिका?-३
२०. 'नहीं ये हो नहीं सकता' गीत वाली फिल्म-४
२१. अमिताभ, जैकी, कैटरीना, मधु, सीमा की 'आई सी यू बेबी' गीत वाली फिल्म-२
२२. 'रंग और नूर की बारात' गीत वाली सुनीलदत्त, मीना कुमारी की फिल्म-३
२४. नसीर, फारूख शेख, स्मिता की फिल्म-३
२६. 'बोल गोरी बोल' गीत वाली सुनीलदत्त, नूतन की फिल्म-३
२७. शाहरूख, माधुरी की 'तू सामने जब आता है' गीत वाली फिल्म-३
२९. 'हम प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7280

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

1 अगस्त 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति
सूर्य	कर्क में
चंद्र	कुंभ में
मंगल	वृष में
बुध	मिथुन में
गुरु	कर्क में
शुक्र	कन्या में
शनि	मीन में
राहु	कुंभ में
केतु	सिंह में

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

लग्नारंभ समय	
सिंह	06.44 बजे से
कन्या	08.56 बजे से
तुला	11.07 बजे से
वृश्चिक	13.21 ब.से
धनु	15.37 बजे से
मकर	17.42 बजे से
कुंभ	19.29 बजे से
मीन	21.02 बजे से
मेष	22.32 बजे से
वृष	00.12 बजे से
मिथुन	02.10 बजे से
कर्क	04.24 बजे से

शनिवार 2026 वर्ष का 213 वा दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास श्रावण (दक्षिण भारत में आषाढ) **पक्ष** कृष्ण
तिथि तृतीया 23.08 बजे को समाप्त।
नक्षत्र शतभिषा 20.46 बजे को समाप्त।
योग शोभन 23.23 बजे को समाप्त।
करण वणिज 10.53 बजे तदनन्तर विष्टि 23.08 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 17.6 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 18° 04'
सूर्य दक्षिणायन
कलि अहर्गण 1872788
जूलियन दिन 2461253.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448 **महीना** सफर
तारीख 17 **विशेष** जयापावर्ती व्रत समाप्त, 1 से 7 शिशु स्तनपान सप्ताह।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया		
काल	05.55 से	07.23 बजे तक		लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक		उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक		शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक		अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक
चर	11.46 से	01.14 बजे तक		चर	11.47 से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक		रोग	01.19 से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक		काल	02.51 से	04.23 बजे तक
काल	04.10 से	05.37 बजे तक		लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: ध्यान की गहराई

बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के व्याख्यान के बाद अमेरिका में प्रसिद्ध हो चले थे। वहां वह घूम-घूमकर वेदांत दर्शन पर प्रवचन दिया करते थे। इस सिलसिले में उन्हें अमेरिका के उन अंदरूनी इलाकों में भी जाना होता था, जहां धर्मांध और संकीर्ण विचारधारा वाले लोग रहते थे। एक बार स्वामीजी को ऐसे ही एक कस्बे में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। एक खुले मैदान में लकड़ी के बक्सों को जमाकर मंच तैयार किया गया था। स्वामीजी ने उस पर खड़े होकर वेदांत, योग और ध्यान पर व्याख्यान देना शुरू किया। बाहर से गुजरने वाले लोग भी उनकी बातें सुनने लगे जिनमें कुछ चरवाहे भी थे। थोड़ी देर में ही उनमें से कुछ ने बंदूकें निकालीं और स्वामीजी की ओर निशाना दागने लगे। कोई गोली उनके कान के पास से गुजरती तो कोई पांव के पास से। नीचे रखे कुछ बक्से तो छलनी हो गए थे। लेकिन इस सबके बावजूद स्वामीजी का व्याख्यान पहले की तरह धाराप्रवाह चलता रहा। न वह थमे न उनकी आवाज कांपी। अब चरवाहे भी वहां ठहर गए। व्याख्यान के बाद वे स्वामीजी से बोले, 'आपके जैसा व्यक्ति हमने पहले नहीं देखा। हमारी गोलीबारी के बीच आपका भाषण ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर हमारा निशाना चूकता तो आपकी जान आफत में पड़ सकती थी।' स्वामीजी ने उन्हें बताया कि जब वह व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्हें बाहरी वातावरण का ज्ञान ही न था। उनका सारा चित्त वेदांत और ध्यान की उन गहराइयों में डूबा हुआ था। वे चरवाहे उनके प्रति नतमस्तक हो गए।

सूडोकु नवताल- 7590

★★★★★ कठिनतम

2						5		
	1			8				9
7					4			
			9			1		
	3						6	
		8			5			
			3					8
5				6			2	
		4						7

Jagrutidaur.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7589 का हल

2	3	6	8	5	1	4	9	7
9	4	5	7	6	3	8	2	1
1	7	8	2	9	4	6	5	3
3	1	9	6	7	2	5	4	8
5	6	2	1	4	8	3	7	9
7	8	4	5	3	9	1	6	2
4	9	1	3	2	5	7	8	6
8	2	7	4	1	6	9	3	5
6	5	3	9	8	7	2	1	4

शब्द पहेली - 8805

बाएँ से दाएँ

1. कवि की रचना, गजल-3
3. अनुमान, अंदाज-3
5. सदपुरुष-2
6. अयोग्य, असंगत -2
8. स्वार्थ, लोभ-4
10. सहयोग, सहकार-3
11. उन्माद, सनक-3
12. भगवान का अराधक-2
13. ठंडक, शीतलता-2
14. दूल्हे के सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी-3
16. चांदी-3
18. गंवारपन, अशिष्टता-4
20. पैंदा, तला-2
22. वर्तमान दिन-2
23. बहने का भाव-3
24. गमन, विदा होना-3

ऊपर से नीचे

1. हुनर, फन, आर्ट-2
2. बल, दम, जोर-3
3. समीप, नजदीक-3
4. गलत का विलोम-2
5. भ्रम, संदेह-3
7. उपनदी, कैनाल-3
8. नशे से भरपूर-4
9. लाख, सौ हजार-2
11. स्वभाव, आदत-4
14. स्वास्थ्य-3
15. इस जगह-2
17. तहजीब, शिष्टता-3
18. इकट्ठा होना-3
19. रेखा, लाइन-3
21. होठ, अधर-2
22. आगमन-2

शब्द पहेली - 8804 का हल

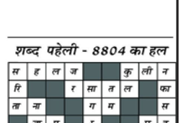

Jagrutidaur.com, Bangalore

कुम्हारीकला-बिंझलगांव मार्ग की पीड़ा कब होगी खत्म ?

लगभग 500 ग्रामीण रोज झेल रहे दलदल का दर्द, किसान, स्कूली बच्चे और मरीज सबसे अधिक प्रभावित- विधायक बोले निर्माण मेरी पहली प्राथमिकता, बारिश थमते ही शुरू होगा काम

पद्मेश न्यूज। लांजी।

जब राहें ही दुश्वारियों का पर्याय बन जाएं, तो विकास के दावे ज़मीन पर घिसटते नज़र आते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा ग्राम पंचायत कुम्हारीकला से बिंझलगांव लोधी चौक को जोडऩे वाले लगभग 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर देखने को मिल रहा है। बारिश के मौसम में यह सड़क अब केवल रास्ता नहीं रही, बल्कि गहरे दलदल और कीचड़ के टापू में तब्दील हो चुकी है। इस मार्ग पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है, जहां स्कूली बच्चे चप्पलें हाथों में थामकर कीचड़ नापने को मजबूर हैं और किसान अपनी जान-माल को जोखिम में डालकर खेतों तक पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत कुम्हारीकला से बिंझलगांव लोधी चौक को जोडऩे वाला करीब तीन किलोमीटर लंबा मार्ग आज ऐसी ही तस्वीर बयां कर रहा है। बरसात ने इस सड़क को दलदल में बदल दिया है। हालात ऐसे हैं कि यहां हर कदम जोखिम से भरा है। स्कूली बच्चे गिर रहे हैं, किसानों के वाहन कीचड़ में धंस रहे हैं, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो गया है और आपातकालीन सेवाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहीं। लगभग 500 ग्रामीण प्रत्यक्ष रूप से इस मार्ग की बदहाली का खामियाजा भुगत रहे हैं। सबसे दर्दनाक स्थिति दो दिन पहले सामने आई, जब गांव के निवासी राजकुमार भीमटे की पत्नी, जो पूर्व जनपद सदस्य भी रह चुकी थीं, का निधन हो गया। सड़क कीचड़ से इस कदर लबालब थी कि एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिजनों और ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर को हाथों में उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से घर तक पहुंचाया। यह घटना केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जहां सड़क की स्थिति जीवन और मृत्यु के बीच भी बाधा बन जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) के अंतर्गत आता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा दो बार सर्वे भी किया जा चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका। यही कारण है कि जिम्मेदारी तय होने के बावजूद समाधान जमीन पर नहीं उतर पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र स्थायी समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण दो दिन बाद मार्ग बंद करने का निर्णय लेने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

क्या कहते हैं ग्रामीण...

गांव के तोमेश्वर बापुरे बताते हैं कि ग्राम पंचायत कुम्हारीकला के लगभग 95 प्रतिशत किसानों की कृषि भूमि इसी मार्ग पर स्थित है। रोजाना 200 से 300 किसान और ग्रामीण खेती-किसानी के कार्यों से इस सड़क का उपयोग करते हैं। लेकिन बरसात शुरू होते ही यह रास्ता आवागमन के बजाय संघर्ष का पर्याय बन जाता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क का निर्माण हो जाता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। इसी मार्ग पर रहने वाले आशीष सिल्हारे का कहना है कि समस्या केवल बारिश की नहीं, बल्कि सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव की भी है। उनके अनुसार मई माह में जहां मुरूम डाला जाना चाहिए था, वहां मिट्टी डाल दी गई, जिससे पहली ही बारिश में पूरा मार्ग दलदल बन गया। अब दोपहिया वाहन फंस रहे हैं, बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं और ग्रामीणों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है।

सचिव बोले....समतलीकरण कराया था, बारिश और भारी वाहनों ने बिगाड़ी स्थिति

ग्राम पंचायत सचिव नंदकुमार भटेरे ने बताया कि करीब दो माह पहले पंचायत द्वारा मुरूम डालकर मार्ग का समतलीकरण कराया गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश और ट्रैक्टरों सहित भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क फिर दलदल में बदल गई। उन्होंने बताया कि स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और संबंधित विभाग के माध्यम से समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। सचिव ने यह भी कहा कि सड़क पंचायत के अधीन नहीं है, इसलिए स्थायी निर्माण संबंधित विभाग द्वारा ही कराया जाना संभव है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लगातार सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज होने से प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित होती हैए हालांकि पंचायत समस्या के समाधान के लिए समन्वय बनाकर काम कर रही है।

विधायक ने दिलाया भरोसा..यह सड़क मेरी पहली प्राथमिकता

क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि कुम्हारीकला से बिंझलगांव जाने वाले इस मार्ग की समस्या उनके संज्ञान में है और सड़क निर्माण उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा लगातार हो रही बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। हमारा प्रयास है कि बारिश का दौर थमते ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को लंबे समय तक सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।

कटंगनाला के पास अज्ञात बाइक की टक्कर से युवक घायल, चालक मौके से फरार

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार, 31 जुलाई को सालेटेकरी रोड स्थित कटंगनाला के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकचंद हनोते (38) पिता ताराचंद हनोते, निवासी ग्राम कुम्हारी खुर्द, अपने मौसाजी के गांव नंदोरा घोटी से सुबह करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कटंगनाला के समीप लांजी की ओर से तेज गति से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लोकचंद सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जबकि हादसे के बाद अज्ञात बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से घायल को सिविल अस्पताल लांजी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत पर निगरानी रखी। घटना के बाद क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के प्रभावी उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

राष्ट्रसेविका समिति ने भानेगांव में मनाया गुरु पूजन उत्सव

लक्ष्मीबाई केलकर के जीवन और संगठन के उद्देश्य से कराया परिचय

पद्मेश न्यूज। लांजी। राष्ट्रसेविका समिति द्वारा 31 जुलाई को क्षेत्र के ग्राम भानेगांव स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में गुरु पूजन उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेविकाओं एवं मातृशक्ति ने भाग लेकर भगवा ध्वज का पूजन किया तथा राष्ट्र, समाज और संस्कारों के प्रति समर्पण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शारदा बल्ले दीदी एवं मुख्य वक्ता लांजी खंड कार्यवाहिका श्रीमती नीलम भर्रे दीदी रहीं। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन भानेगांव प्रमुख श्रीमती वंदना आठवले दीदी तथा व्यवस्था प्रमुख श्रीमती बबिता विश्वास ने किया।

मुख्य वक्ता श्रीमती नीलम भर्रे दीदी ने राष्ट्रसेविका समिति की आद्य प्रमुख संचालिका श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, मातृशक्ति के जागरण और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से संगठन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रसेविका

समिति महिलाओं में सेवा, संस्कार, संगठन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए समाज को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है।

उन्होंने भगवा ध्वज को गुरु मानने की परंपरा का महत्व बताते हुए कहा कि व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवा ध्वज त्याग, तपस्या, शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति जैसे शाश्वत आदर्शों का प्रतीक है। यही कारण है कि समिति में किसी व्यक्ति विशेष के बजाय भगवा ध्वज को गुरु के रूप में पूजनीय माना जाता है।

कार्यक्रम में लांजी शाखा से दुर्गा रामटेककर दीदी, मीना बिलगौर दीदी, गुनवंती दमाहे दीदी, सुग्रता डकाटे दीदी, वर्षा नाकतोडे दीदी, कांता नरताम दीदी, लावन्या चन्ने एवं हिमानी कश्यप की विशेष उपस्थिति रही। वहीं भानेगांव शाखा से रेशमा विश्वास, सलोनी बेदरे, भाव्या बुराडे एवं सलोनी बुराडे सहित अनेक सेविकाएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति और संगठन के आदर्शों के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित सेविकाओं ने समाज में सेवा, संस्कार और संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए नियमित रूप से समिति की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

डिजिटल वोटिंग से चुने गए भारत माता पब्लिक स्कूल के यंग लीडर्स

पद्मेश न्यूज। लांजी। भारत माता पब्लिक स्कूल लांजी में शुक्रवार को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल पार्लियामेंट चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ डिजिटल वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान कर अपने छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया। चुनाव का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ विकसित करना था। चुनाव में हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन और कल्चरल कैप्टन के पदों के लिए मतदान कराया गया। मतदान से पहले सभी प्रत्याशियों ने विद्यार्थियों के बीच अपना परिचय दिया तथा विद्यालय के विकास और छात्र हित में अपने विचार एवं योजनाएं साझा कीं। विद्यार्थियों ने भी उम्मीदवारों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विद्यालय में पहली बार डिजिटल वोटिंग मशीन का उपयोग किए जाने से विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इससे उन्हें वास्तविक चुनाव जैसी मतदान प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त हुआ। प्राचार्य, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन की निगरानी में पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतदान समाप्त होने के बाद डिजिटल माध्यम से मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए, जिनका विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया।

चुनाव परिणाम में हेड बॉय: अंश ठाकरे, हेड गर्ल: परिधि तुरकर, स्पोर्ट्स कैप्टन: प्रवींद्र कुशले, कल्चरल कैप्टन: मौली सोमनकर चुनें गए। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, आत्मविश्वास और सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी। साथ ही विद्यार्थियों से कहा गया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों के लिए प्रेरणा बनने, टीम भावना से कार्य करने और विद्यालय परिवार की जिम्मेदारी निभाने में निहित है। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि स्कूल पार्लियामेंट चुनाव केवल छात्र प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह विद्यार्थियों के लिए लोकतंत्र, जिम्मेदारी और नेतृत्व के मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण शिक्षण अनुभव भी बना। इस आयोजन ने विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य के नेतृत्व के लिए प्रेरित किया।

कोलकाता में दिखेगा रीवा के कराटेबाजों का दम, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में तोषराम कनोजे समेत तीन खिलाड़ी करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

पद्मेश न्यूज। लांजी। लांजी क्षेत्र के निवासी एवं वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, रीवा में जिला खेल प्रशिक्षक (कराटे कोच) के पद पर पदस्थ तोषराम कनोजे अपने प्रशिक्षित खिलाडियों शिवा कुशवाहा एवं विनेश कनोजे के साथ 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप-इंडियन चैलेंजर्स कप 2026 में हिस्सा लेंगे। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता विभिन्न देशों के कराटे खिलाड़ियों को एक मंच पर लाएगी, जहां खिलाड़ी अपनी तकनीक, कौशल और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रीवा के तीनों खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठिन अभ्यास और नियमित प्रशिक्षण के बाद इस प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी पूरी की है। प्रशिक्षक तोषराम कनोजे के मार्गदर्शन में तैयार हुए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं। क्षेत्रवासियों एवं खेल प्रेमियों ने तीनों खिलाडियों को शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास जताया है कि वे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर

पदक हासिल करेंगे और रीवा, मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।

दादा कोटेश्वर धाम में प्रारंभ हुआ संगीतमय शिव नाम जप एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण

पद्मेश न्यूज। लांजी। श्रावण मास के पावन अवसर पर दादा कोटेश्वर धाम, लांजी में 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक एक माह का विशेष धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दौरान प्रतिदिन ? नमः शिवाय नाम जप संगीतमय संकीर्तन, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक एवं महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संगीतमय शिव नाम जप एवं संकीर्तन, दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण तथा शाम 4:00 बजे से रुद्राभिषेक एवं महाआरती संपन्न कराया जा रहा है। श्रावण मास के इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान शिव की आराधना का लाभ लेने की अपील आयोजन समिति ने की गई है। यह संपूर्ण अभियान समस्त ग्रामवासियों एवं ग्राम समितियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अभिनंदन लाइफ फाउंडेशन सेवा सहयोग प्रदान कर रहा है, अभियान के संयोजक अध्यक्ष झनकार किरनापुरे ने कहा कि यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ समाज में सेवा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता का सशक्त संदेश देने का माध्यम बनेगा। सभी धर्म प्रेमियों से उक्त आयोजन मे अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की गई है।

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

दतिया उपचुनाव : ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत

- 8.76 प्रतिशत कम वोटिंग ने बढ़ाई चिंता - दिग्गजों की साख दांव पर!

भोपाल। दतिया उपचुनाव के लिए गुरुवार को 71.44 प्रतिशत मतदान हुआ, जो वर्ष 2023 के मतदान से लगभग 8.76 फीसदी कम है। कम मतदान ने भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही दोनों पार्टियों के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही इस उपचुनाव के कारण प्रदेश के दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर है। यानी नतीजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की राजनीतिक साख पर भी असर डालेंगे।

मध्य प्रदेश के दतिया में उप चुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। फिर भी मतदान का आंकड़ा 2023 के विधानसभा चुनाव से करीब 9 फीसदी कम रहा। अब दतिया उपचुनाव में वोटिंग के बाद जीत के दावे भी शुरू हो गए है। बंपर मतदान के बाद बीजेपी-कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत की बात कह रही है, लेकिन किसके दावों में दम है, यह तीन अगस्त को पता चल जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है, जो सरकार की नीतियों और विकास का परिणाम होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि

इस बार भाजपा ने जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरूपयोग कर चुनाव जीतने का सपना देखा है, उसे मतदाताओं से पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत कर भाजपा और राज्य सरकार के गलत निर्णयों का जवाब देगी।

प्रतिष्ठा की लड़ाई

दतिया उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस की ताकत आजमाने का बड़ा पैमाना माना जा रहा है। इसका परिणाम प्रदेश की राजनीति को कई संदेश देगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया जिला भाजपा संगठन ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इसे भाजपा के लिए बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा के लिए इस सीट को जीतना प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यदि भाजपा सीट कांग्रेस से छीनने में सफल रहती है तो इसे सरकार के कामकाज, संगठन की रणनीति और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर जनता की मुहर के रूप में देखा जाएगा। वहीं, भाजपा की फिर हार की स्थिति में विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के लिए भी यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। दतिया उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है और वर्षों तक उन्होंने इस क्षेत्र में मजबूत संगठन खड़ा किया। माना जा रहा था कि उपचुनाव में भाजपा उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। टिकट बदलने के फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी सामने आई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। बाद में नरोत्तम मिश्रा स्वयं तिवारी के समर्थन में प्रचार में उतरे और घर-घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। ऐसे में यदि भाजपा जीतती है तो इसे क्षेत्र में उनकी संगठनात्मक पकड़ और प्रभाव कायम रहने के संकेत के रूप में देखा जाएगा। वहीं, हार की स्थिति में टिकट चयन और स्थानीय असंतोष को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

पटवारी के लिए अग्नि परीक्षा

दूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी यह उपचुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। यदि कांग्रेस यह सीट बचाने में सफल रहती है तो इसे पटवारी की रणनीति और विपक्ष की सक्रियता की बड़ी सफलता माना जाएगा। वहीं हार कांग्रेस संगठन के लिए बड़ा झटका मानी जाएगी। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहे हैं। एक आपराधिक मामले में अदालत द्वारा उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। कांग्रेस ने इस बार दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है।

भोपाल की पुश्तैनी जमीन को लेकर मेनका गांधी और ममेरे भाई में कानूनी जंग

- हुजूर तहसील के लाऊखेड़ी क्षेत्र स्थित पैतृक जमीन के नामांतरण में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

भोपाल। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी और उनके ममेरे भाई वी.एन. सिंह के बीच भोपाल की पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामला भोपाल की हुजूर तहसील के लौखेड़ी क्षेत्र स्थित पुश्तैनी भूमि के नामांतरण (म्यूटेशन) से जुड़ा है। इस विवाद में मेनका गांधी और उनकी बहन अंबिका शुक्ला ने वी.एन. सिंह के खिलाफ अपील दायर की है। उनका आरोप है कि विवादित जमीन के नामांतरण से संबंधित आदेश उन्हें पक्षकार बनाए बिना ही पारित कर दिया गया, जबकि पैतृक संपत्ति में उनका भी वैधानिक हित है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नामांतरण की कार्रवाई पूरी कर दी गई। पहले एकलपीठ से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में आने वाला निर्णय न केवल संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पुश्तैनी संपत्ति के विवादों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और नामांतरण प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाल सकता है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें देश की चर्चित राजनीतिक हस्ती मेनका गांधी की पुश्तैनी संपत्ति का विवाद न्यायालय तक पहुंचा है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है।

अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

अपीलकर्ताओं का तर्क है कि पैतृक संपत्ति में उनका हित होने के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एकलपीठ से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों ने युगलपीठ का रुख किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

छतरपुर वृत में भी दोबारा होगी पदोन्नति समिति की बैठक

– कर्मचारियों से मांगे गए अभ्यावेदन

भोपाल। वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में अब छतरपुर वृत भी जांच के दायरे में आ गया है। खंडवा के बाद छतरपुर वृत में भी पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य वन संरक्षक ने इस संबंध में पत्र जारी कर वन कर्मचारियों से अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं।

मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने आरोप लगाया कि वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बडियां हुई हैं। उनका कहना है कि कई पात्र वन कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह गए, जबकि अपात्र कर्मचारियों को अधिकारियों की कृपा से पदोन्नति का लाभ मिल गया। पांडे ने बताया कि शिकायतों के बाद खंडवा वृत में पदोन्नति सूची का पुनरीक्षण किया गया, जिसमें 94 नए वन कर्मचारियों को शामिल कर पदोन्नति दी गई। अब छतरपुर वृत में भी पदोन्नति समिति की बैठक दोबारा बुलाए जाने का निर्णय इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हुई हैं। वन कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री से पूरे प्रदेश के सभी वन वृतों की पदोन्नति प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही पात्र होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को न्याय दिलाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। मंच के अनुसार, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और रीवा सहित कई वृतों में भी पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। यदि इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है, तो अन्य वृतों में भी पदोन्नति सूचियों की समीक्षा की जा सकती है।

किसानों को बड़ा झटका, मिट्टी और बीज परीक्षण लोक सेवा गारंटी से बाहर

- समय पर रिपोर्ट और अपील का अधिकार खत्म

भोपाल। प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने किसानों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुविधा वापस ले ली है। अब खेतों की मिट्टी परीक्षण और प्रमाणित (सर्टिफाइड) बीज नमूना परीक्षण की सेवाएं मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में नहीं रहेंगी। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए तय समय सीमा में रिपोर्ट मिलने की कानूनी गारंटी और देरी होने पर अपील का अधिकार भी समाप्त हो गया है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने 29 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर वर्ष 2017 में अधिसूचित इन दोनों सेवाओं को डी-नोटिफाई (विलोपित) कर दिया है। अब किसान इन सेवाओं में देरी होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई या अपील नहीं कर सकेंगे।

9 साल पुरानी व्यवस्था समाप्त

राज्य सरकार ने 22 जुलाई 2017 को किसानों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिट्टी परीक्षण और प्रमाणित बीज परीक्षण को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया था। इससे किसानों को निर्धारित समय सीमा में परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना विभाग की कानूनी जिम्मेदारी थी। इसके तहत मिट्टी नमूना परीक्षण रिपोर्ट 30 कार्य दिवस में देना अनिवार्य था। सर्टिफाइड बीज नमूना परीक्षण रिपोर्ट 60 कार्य दिवस में उपलब्ध कराई जानी थी। इन सेवाओं के लिए संबंधित प्रयोगशाला अधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया था।

देरी पर मिलता था अपील का अधिकार

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत यदि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं मिलती थी तो किसान अपील कर सकते थे। मिट्टी परीक्षण के मामलों में पहली अपील जिला उप संचालक और दूसरी अपील संभागीय संयुक्त संचालक के समक्ष की जा सकती थी। बीज परीक्षण के मामलों में पहली अपील संभागीय उप संचालक और दूसरी अपील संयुक्त संचालक के समक्ष करने का प्रावधान था। यदि अधिकारी समय पर सेवा नहीं देते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई और दंड का भी प्रावधान था।

अब किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

नई अधिसूचना लागू होने के बाद मिट्टी और बीज परीक्षण सेवाओं के लिए अब कोई वैधानिक समय-सीमा लागू नहीं रहेगी। यानी रिपोर्ट कब मिलेगी, इसकी कानूनी बाध्यता समाप्त हो गई है। यदि रिपोर्ट में देरी होती है तो किसान लोक सेवा गारंटी कानून के तहत न तो अपील कर सकेंगे और न ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर पाएंगे।

किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला

यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब प्रदेश में किसान विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसे में किसानों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी से बाहर किए जाने को कृषि प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन माना जा रहा है। इससे समयबद्ध सेवाओं की कानूनी गारंटी समाप्त होने के कारण किसानों की जवाबदेही तय कराने की व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है।

मुख्य सचिव, सीएम सचिवालय के अफसरों के स्टाफ बदले

भोपाल। अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाए जाने और उनके दिल्ली जाने के बाद नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के स्टाफ में आंशिक बदलाव हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी नए अफसरों की पदस्थापना के साथ उनके स्टाफ के अफसर, कर्मचारी बदले गए हैं। इन सीनियर अफसरों के स्टाफ में हुए बदलाव में उनके निज सचिव और स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर नए कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं। सभी बदले गए अधिकारी कर्मचारी मंत्रालय सेवा के हैं। अभी कुछ और बदलाव हो सकते हैं।

इन अधिकायरों के बदले स्टाफ

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद मुख्य सचिव बर्णवाल के निज सचिव की जिम्मेदारी अब अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निज सचिव का काम देख रहे हरिशंकर भार्गव संभालेंगे। इसी तरह अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सचिन सिन्हा के निज सचिव पद पर सामान्य प्रशासन पूल में पदस्थ शेख हबीब को पदस्थ किया गया है। इनके अलावा प्रमुख सचिव राजस्व और नर्मदा घाटी विकास विभाग डॉ ई. रमेश कुमार के निज सचिव पद पर संजय कुमार जोशी, स्टेनोटाइपिस्ट पद पर योगेश गोयल की पदस्थापना की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ किए गए सचिव डॉ सुदाम खाड़े के स्टेनोग्राफर के रूप में सतीश कुमार शुक्ला और मुख्यमंत्री के उपसचिव सुधीर कोचर के स्टाफ में स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में पंकज उइके को पदस्थ किया गया है। इस आदेश के बाद अब मंत्रालय में मुख्य सचिव के स्टाफ में पदस्थ कर्मचारी इधर-उधर किए जा सकते हैं।

हाईवे पर ग्रीन कवर में मप्र देश में सबसे आगे

- 5 साल में नेशनल हाईवे पर लगाए 39 लाख पौधे

भोपाल । केंद्र सरकार की हरित राजमार्ग नीति 2015 के तहत देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा रहा है। राज्यसभा में सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी जानकारी के अनुसार, बीते पांच सालों में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 39.26 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। पूरे देश में पिछले पांच वर्षों में लगभग 1.32 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3.61 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस राष्ट्रीय आंकड़े में अकेले मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 11 प्रतिशत है।

सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सबसे कम पौधारोपण मेघालय में हुआ है, जहां 0.02 लाख (2,000) पौधे लगाए गए। दूसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जहां कुल 0.03 लाख (3,000) पौधे लगाए गए। तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है, जहां 5 वर्षों में कुल 0.15 लाख (15,000) पौधे रोपे गए। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां 0.41 लाख (41,000) पौधे लगाए गए। पांचवें स्थान पर मणिपुर है, जहां 0.50 लाख (50,000) पौधे लगाए गए हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश को छोडक़र केवल पूर्ण राज्यों की बात करें, तो सबसे कम पौधारोपण वाले राज्यों में मणिपुर के बाद केरल आता है, जहां 5 वर्षों में कुल 0.66 लाख (66,000) पौधे लगाए गए हैं।)

पौधों की सुरक्षा और नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। पौधों की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसके साथ ही, कम क्षेत्र में तेजी से सघन वन विकसित करने के उद्देश्य से मियावाकी पौधारोपण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हाईवे बनाने के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पौधारोपण और साइंटिफिक ट्री ट्रांसप्लांटेशन (वृक्ष प्रत्यारोपण) किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में रीसाइकिल की गई सामग्रियों और औद्योगिक अपशिष्टों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। सडक़ों की परतों में प्लास्टिक अपशिष्ट, फ्लाई ऐश/पॉन्ड ऐश, रीक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट, क्रम्ब रबर और बायो-बिटुमेन का उपयोग हो रहा है। सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बांस के क्रैश बैरियर और जूट/नारियल जटा से निर्मित प्राकृतिक भू-वस्त्र (जियो टेक्सटाइल्स) का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल संरक्षण हेतु सडक़ निर्माण कार्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपचारित जल का उपयोग किया जा रहा है।

हाईवे निर्माण के साथ ही पौधारोपण का भी बजट में प्रावधान

ग्रीन हाइवे पॉलिसी के अंतर्गत पौधारोपण और पर्यावरणीय शमन कार्यों के लिए अलग से वित्तीय कठिनाई नहीं रखी गई है। वृक्षारोपण की लागत संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की कुल स्वीकृत लागत में ही शामिल होती है। यह खर्च राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित समग्र निधि से किया जाता है। अलग से या विशेष अभियानों के अंतर्गत किए जाने वाले स्टैंडअलोन पौधारोपण का खर्च भी राजमार्ग विकास की स्वीकृत एकीकृत निधि से वहन किया जाता है।

प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग, आईजी ग्वालियर रिटायर

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी है। प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग उमाकांत उमराव और ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना शुक्रवार को रिटायर हो गए। दोनों के रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार जल्द ही उनकी जगह नई पदस्थापना के आदेश जारी कर सकती है।

उमाकांत उमराव के पास पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की जिम्मेदारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह विभाग मंत्री लखन पटेल से वापस लेकर अपने पास रखा था। ऐसे में अब इस विभाग की जिम्मेदारी किसी प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है।

अगस्त के अंत में पुलिस विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारी भी रिटायर होंगे। इनमें डीजी अजय कुमार शर्मा (1989 बैच), डीजी आशुतोष राय (1994 बैच) और एडीजी ए. साईं मनोहर (1995 बैच) शामिल हैं। इनके अलावा आईजी सागर मिथलेश शुक्ला भी अगस्त में रिटायर होंगे। ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना के साथ शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी शशिकांत शुक्ला भी रिटायर हो रहे हैं। वहीं, आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा अक्टूबर में रिटायर होंगी।

इस साल रिटायर होंगे ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी

आशीष श्रीवास्तव (केंद्रीय गृह मंत्रालय) – अक्टूबर

अरुणा गुप्ता (सचिव, लोकायुक्त) – अक्टूबर

सुरेश कुमार (चंबल संभाग आयुक्त) – सितंबर

ललित दाहिमा (सचिव, राजस्व मंडल) – दिसंबर

चंद्रशेखर वालिम्बे (अपर सचिव, सीएम कार्यालय) – नवंबर

रवींद्र चौधरी (अपर सचिव, नर्मदा घाटी विकास) – नवंबर

संजय कुमार मिश्रा (अपर सचिव, आयुष विभाग) – नवंबर

केदार सिंह (पूर्व कलेक्टर, शहडोल) – नवंबर

जीएस धुर्वे (अपर कलेक्टर, बालाघाट) – अगस्त

इन वरिष्ठ अधिकारियों के रिटायर होने के बाद राज्य सरकार को कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां करनी होंगी। इससे प्रशासनिक और पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तबादले और नई जिम्मेदारियां तय होने की संभावना है।

आदिवासी वोट साधने में जुटी कांग्रेस, रिसर्च पेपर से बनेगी चुनावी रणनीति

- दो साल पहले ही बनाई विशेष समिति, शिक्षा-रोजगार, जल-जंगल-जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर तैयार होंगे अध्ययन पत्र

- भाजपा के मजबूत होते आधार को चुनौती देने की तैयारी

भोपाल । मध्यप्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट हमेशा सत्ता की चाबी माने जाते रहे हैं। यही वजह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी दो साल से ज्यादा का समय होने के बावजूद कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी का सबसे बड़ा फोकस आदिवासी समाज पर कर दिया है। पार्टी ने केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि रिसर्च आधारित रणनीति तैयार करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश में गठित आदिवासी समिति अब आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, जल-जंगल-जमीन, वन अधिकार, संवैधानिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे विषयों पर रिसर्च पेपर तैयार किए जाएंगे। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर सरकार को घेरा जाएगा और चुनावी एजेंडा भी तय होगा।

समिति ने अगले दो वर्षों का रोडमैप तैयार किया है। समिति केवल दस्तावेज तैयार नहीं करेगी, बल्कि प्रदेशभर के आदिवासी क्षेत्रों में संवाद अभियान भी चलाएगी। विभिन्न जिलों से तथ्य जुटाने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर राजनीतिक व संगठनात्मक अभियान आगे बढ़ेगा। समिति की कमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के हाथ में है। इसके अलावा विक्रांत भूरिया, बाला बच्चन, ओंकार सिंह मरकाम, फुंदेलाल मार्को, झूमा सोलंकी, संजय उइके, सुनील उइके और डॉ. अशोक मर्सकोले जैसे आदिवासी नेता सदस्य हैं। बैठक में तय हुआ कि अलग-अलग विषयों पर अध्ययन कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

एक समय आदिवासी समाज कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में कांग्रेस अब पुराने सामाजिक आधार को दोबारा मजबूत करने के लिए फॉर्मूला-47 की तर्ज पर माइक्रो प्लानिंग कर रही है। पार्टी का मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में मुद्दा आधारित राजनीति उसे फिर बढ़त दिला सकती है।

सरकार को मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

समिति की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वनाधिकार, विस्थापन, जल-जंगल-जमीन और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। साथ ही इन विषयों को चुनावी घोषणा पत्र और जनसंपर्क अभियान का भी हिस्सा बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जबकि करीब 80 से अधिक सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक प्रभाव रखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2028 की सत्ता की लड़ाई में भी आदिवासी वोट सबसे निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह पहल केवल संगठनात्मक कवायद नहीं, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव की लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

एक पखवाड़े में होगा आरटीओं में पेंडिंग कामों का निपटारा!

भोपाल। प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में जनता के कामों की पेंडेंसी दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा।

उपायुक्त किरण शर्मा ने बताया कि आरटीओ यह अभियान कार्यालय स्तर पर या शिविर लगाकर करेंगे। परिवहन विभाग की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हैं, इनमें दस्तावेज की कमी से लेकर जो भी थोड़ी बहुत कमी या बड़ी समस्या होगी, उसका अधिकारी निराकरण करेंगे। सभी जिलों से आवेदनों का डेटा भी मांगा गया है और कई जिलों से पहुंचना शुरू हो गया है।

सेवाएं ऑनलाइन, दलाल तंत्र बना मुसीबत

परिवहन विभाग में वाहन रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, परमिट, फिटनेस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेड सर्टिफिकेट, प्रदूषण जांच केंद्र आवेदन, मोटर ड्राइविंग स्कूल, ऑल इंडिया परमिट जैसी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन कोई भी क्वेरी आने पर वाहन स्वामी को कार्यालय बुलाया जाता है। चेक पोस्ट से लेकर आरटीओ कार्यालयों तक सक्रिय दलाल तंत्र भी परेशानी का सबब बना हुआ है। दफ्तर के बाहर छोटी-छोटी टेबल लगाकर बैठे एजेंट अस्थाई लाइसेंस के बदले हजार तो स्थाई लाइसेंस के लिए तीन हजार रुपये तक वसूलते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 10वें नंबर पर, 17 मेडल जीते

लवप्रीत को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर सीमा ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीता

ग्लासगो, एजेंसी।

लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में आठवें दिन भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया है। वहीं, महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रॉन्ज हासिल किया। गुरुवार देर रात लवप्रीत ने पुरुष वेटलिफ्टिंग की 110 ˝ वेट कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 176 और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम वजन उठाया। दूसरी ओर सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर थ्रो करके किया। इस ब्रॉन्ज के बाद भारत के 17 मेडल हो गए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत 10वें स्थान पर है।

लवप्रीत महज एक किलो से गोल्ड चूके

लवप्रीत ने स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। वे गोल्ड मेडल जीतने के बेहद करीब थे, लेकिन न्यूजीलैंड के डेविड डेविड एंड्रयूज से महज एक किग्रा के अंतर से पिछड़ गए। लवप्रीत ने कुल 388 किग्रा (स्नैच में 176 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 212 किग्रा) वजन उठाया। वहीं, न्यूजीलैंड के लिटी ने क्लीन एंड जर्क में गेम्स रिकॉर्ड के साथ कुल 389 किग्रा (166 किग्रा + 223 किग्रा) वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ ने 356 किग्रा (165 किग्रा + 191 किग्रा) के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

मां बनने के बाद सीमा की वापसी

27 साल की सीमा ने मां बनने के बाद गेम्स में शानदार वापसी की है। सीमा ने अपने चौथे, पांचवें और छठे प्रयास में फाउल किया, लेकिन 58.65 मीटर के थ्रो ने उन्हें पोडियम तक पहुंचा दिया। इस इवेंट में जमैका की सामंथा हॉल (61.66 मीटर) ने गोल्ड और कनाडा की जूलिया टंक्स (60.67 मीटर) ने सिल्वर मेडल हासिल किया। एक अन्य भारतीय निधि रानी 53.19 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

चोट के कारण तीन साल खेल से दूर रहीं

खेल के साथ सीमा भिवानी के चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में Ph.D. भी कर रही हैं। गंभीर घुटने की चोट के कारण उन्हें तीन साल से ज्यादा समय तक खेल से दूर रहना पड़ा, लेकिन लंबी रिहैबिलिटेशन बाद उन्होंने शानदार वापसी की। 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहीं सीमा ने 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2026 में उन्होंने 59.73 मीटर का अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो दर्ज किया और देश की टॉप डिस्कस थ्रोअर में अपनी जगह मजबूत की। उनके प्रदर्शन के दम पर उन्होंने 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई।

विराट ने रहाणे को अपना सबसे भरोसेमंद जोड़ीदार बताया बोले, तुमने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल किया

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने खेल को अलविदा कहने वाले बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह मेरे सबसे भरोसेमंद जोड़ीदार रहे हैं।

विराट ने रहाणे को स्लिप में सबसे सुरक्षित जोड़ी और पसंदीदा पार्टनर के तौर पर याद किया। कोहली ने शानदार कैरियर के लिए रहाणे को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा, आजिंक्य शानदार करियर के लिए बधाई, दोस्त। तुमने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल किया है। तुम्हें अपने सफर पर बहुत गर्व हो सकता है। हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर की कामना है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।

गौरतलब है कि रहाणे का संन्यास भारतीय क्रिकेट के एक बेहद अनुशासित, शांत और जुझारू क्रिकेटर के करियर का समापन है। विराट अलावा कई अन्य खिलाड़ियों ने भी रहाणे के शानदार योगदान को सराहा है। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उन्हें इस पीढ़ी के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक बताया, जिन्होंने सभी फॉर्मेट में देश का प्रतिनिधित्व किया और कुछ बड़े मैचों में सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। वहीं दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने रहाणे की शांत मानसिकता और खेल के प्रति उनके गर्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी विरासत हमेशा भारत को ऑस्ट्रेलिया में उस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत तक ले जाना रहेगी। वहीं, घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए उनके साथी रहे सूर्यकुमार यादव ने रहाणे के साथ मैदान और ड्रेसिंग रूम साझा करना सम्मान की बात बताया, यह कहते हुए कि उनकी शांति, हिम्मत और प्रतिबद्धता ने बहुतों को प्रेरित किया है।

गौरतलब है कि रहाणे के करियर का सबसे यादगार अध्याय 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत रही। तब एडिलेड में पहले टेस्ट में मिली करारी हार और तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के स्वदेश लौटने के बाद, रहाणे ने टीम की कमान संभालते हुए सीरीज में वापसी करते हुए टीम को जीत दिलायी थी। वर्ष 2011 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले अजिंक्य रहाणे ने तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 85 टेस्ट मैचों में 12 शतक और 26 अर्धशतक की बदौलत 5,077 रन बनाए।

अश्विन ने 2027 विश्वकप के लिए भुवनेश्वर को शामिल किया, रोहित को बनाया कप्तान

ग्लासगो । पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने साल 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिए अपनी पसंदीदा भारतीय टीम घोषित कर दी है। हैरानी की बात है कि अश्विन ने इसमें आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अलावा संजू सैमसन और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी शामिल नहीं किया है।

वहीं पिछले काफी समय से टीम से बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में जगह दी है। अश्विन ने अपनी टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी है। टीम में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के अलावा युवा शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है। टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी ईशान को दी गयी हे। युवा वैभव सूर्यवंशी के अलावा अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे को भी टीम में जगह नहीं मिली है। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के अलावा यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल करने पर संशय बना हुआ है।

भारत पदक तालिका में आठवे स्थान पर खिसका, ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर बरकरार

ग्लासगो । भारतीय खिलाड़ियों ने स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में जारी राष्ट्रमण्डल खेलों में अब तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए 17 पदक जीत लिए हैं। इसमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि भारतीय खिलाड़ियों ने आठवें दिन दो पदक जीते पर इसके बाद भी वह पदक तालिका में दो स्थान नीचे खिसक गयी है। भारतीय टीम अब आठवें स्थान पर पहुंच गयी है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम ने अब तक 17 पदक जीते हैं। इसमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।

आठवें दिन भारतीय टीम को पहला पदक भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह ने हासिल किया। लवप्रीत ने पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। लवप्रीत केवल एक किलोग्राम से स्वर्ण नहीं जीत पाये। वहीं, महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा कालीरमन ने कंस्य पदक जीता। सीमा ने 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंकते हुए भारत के लिए इस इवेंट का चौथा कांस्य हासिल किया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 110 पदक जीते हैं, जिनमें 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं, और वह शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं इंग्लैंड ने एक स्थान का फायदा उठाते हुए कनाडा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं इंग्लैंड के अब 15 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 65 पदक हो गए हैं।

अब घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड की ओर से खेलेंगे जम्पा

सिडनी । ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा अब घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड की ओर से खेलेंगे। अब तक वह न्यू साउथ वेल्स की ओर से खेलते आये थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। ज़म्पा ने ये कदम अपनी ट्रेनिंग सुविधाओं के करीब रहने के लिए उठाया है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन में अभ्यस स्थल उनके घर के करीब है। टीम में बदलाव से उनके घरेलू क्रिकेट करियर में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इससे उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन स्थापित होगा।

ज़म्पा के लिए क्वींसलैंड उनके घरेलू करियर की तीसरी राज्य टीम होगी। इससे पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओ से सात साल खेला था। इसके बाद वह न्यू साउथ वेल्स चले गए थे। इस अनुभवी स्पिनर के होने से टीम को बढ़त मिलेगी। अब वह क्वींसलैंड की ओर से खेलते हुए मार्नस लाबुशेन, माइकल नेसर और जेवियर बार्टलेट जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंधित खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे, जिससे टीम की गहराई और अनुभव दोनों में वृद्धि होगी। उनका आगमन शामिल होने से क्वींसलैंड का स्पिन आक्रमण भी बेहतर होगा। ।

क्वींसलैंड क्रिकेट के जनरल मैनेजर हाई परफॉर्मेंस, बेनेट किंग ने ज़म्पा के टीम में आने पर खुशी जतायी है। उन्होंने कहा, हमें बेहद खुशी है कि एडम जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका अनुभव, खेल की समझ और शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता निस्संदेह हमारे युवा खिलाड़ियों और समग्र ग्रुप को बड़ा फायदा पहुंचाएगी। किंग ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी ज़म्पा को ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के उनके लक्ष्यों को पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि, ज़म्पा के रेड-बॉल क्रिकेट में भविष्य को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं। पिछले दो सीज़न में, उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के कारण उन्होंने केवल दो घरेलू मैच खेले हैं, और पिछले तीन सीज़न में तो उन्होंने सिर्फ एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है। क्वींसलैंड में भी उनकी रेड-बॉल टीम में जगह बनाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि साथी लेग-स्पिनर मिशेल स्वेपसन पहले से ही टीम के मुख्य रेड-बॉल स्पिनर के रूप में स्थापित हैं।

आईसीसी ने साल 2027 एकदिवसीय विश्वकप के लिए नया प्रारुप घोषित किया

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने साल 2027 एकदिवसीय विश्वकप के लिए नया प्रारुप घोषित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में कुल 57 मैच खेले जाएंगे। इसमें 12 ऐतिहासिक और नए मैदानों को भी शामिल किया गया है।

इस टूर्नामेंट के अधिकतर मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में खेले जाएंगे। यहां आठ शहरों के स्टेडियमों में मैचों का आयोजनर होगा। इनमें जोहान्सबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम, त्स्वाने का सेंचुरियन, केप टाउन का न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड और डर्बन का किंग्समीड मैदान अहम रहेगा। इसके अलावा गकेबरहा का सेंट जॉर्ज पार्क, ब्लोएमफॉन्टेन का मंगाउंग ओवल, पार्ल का बोलैंड पार्क और कुगोम्पो सिटी स्थित बफेलो पार्क में भी मैच होंगे। वहीं सह मेजबान जिम्बाब्वे के तीन मैदानों पर मुकाबले रखे गये हैं। राजधानी हरारे का हरारे स्पोर्ट्स क्लब, बुलवायो का क्वींस स्पोर्ट्स क्लब और विक्टोरिया फॉल्स का नया फाले मोसी-ओ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गौरतलब है कि जिम्बाब्वे भी साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका के साथ विश्व कप में सह मेजबान रहा है।

एशियन लीजेंड्स लीग में कल होगा इंडियन रॉयल्स और पाकिस्तान पैंथर्स में मुकाबला

मुम्बई । भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का प्रशंसकों को हमेशा से ही इंतजार रहता है। वहीं अब रिटायर्ड क्रिकेटरों की की एशियन लीजेंड्स लीग में ये दोनो देशों की टीमें 2 अगस्त को फिर आमने-सामने होंगी। इसमें भारत के पूर्व क्रिकेटरों की इंडियन रॉयल्स का मुकाबल पाकिस्तान पैंथर्स से होगा।

पहले ये टूर्नामेंट 2 जून 2026 से केन्या के नैरोबी स्थित जिमखाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला था पर अब इसे अगस्त में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला श्रीलंका लायंस और अफगानिस्तान पठान्स के बीच खेला जाएगा। पहले सत्र में लीग को मिली शानदार सफलता को देखते हुए लीग इस बार और भी बड़े स्तर पर वापसी करने जा रही है। ये सभी मुकाबले जाम्बिया के लोटस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।

पाक बल्लेबाज युसुफ के नाम है एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक का रिकार्ड

लाहौर । पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद युसूफ के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा रिकार्ड है जो आज तक कोई क्रिकेटर नहीं तोड़ पाया है। मोहम्मद युसूफ एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इस पाक क्रिकेटर के नाम 9 टेस्ट शतक का रिकार्ड है जो उसने साल 2006 में बनाया था। उनके साथ ही रिकी पोंटिंग, सर विवियन रिचर्ड्स, अरविंद डिसिल्वा और सचिन तेंदुलकर के नाम भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है।

मोहम्मद युसूफ - साल 2006 में यूसुफ ने11 मैचों की 19 पारियों में, उन्होंने 99.33 की अविश्वसनीय औसत से 1,788 रन बनाए। 2,854 गेंदों का सामना करते हुए, उन्होंने 202 रनों का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया और 222 चौकों तथा 12 छक्कों की मदद से 9 शतक का रिकॉर्ड बनाया। उनके नाम 3 अर्धशतक भी हैं। वह इस साल केवल 1 बार शून्य पर आउट हुए।

रिकी पोंटिंग - साल 2006 में ही पोंटिंग ने 2006 में केवल 10 मैचों की 18 पारियों में जमकर रन बनाये। 3 बार नाबाद लौटते हुए उन्होंने 88.86 की शानदार औसत से 1,333 रन बनाये। 196 के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 7 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए। बिना किसी शून्य के, उन्होंने पूरे साल विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाये रखा।

विवियन रिचर्ड्स - वहीं साल 1976 में वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स ने अपनी आक्रामक टेस्ट बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था। तब 11 मैचों की 19 पारियों में, रिचर्ड्स ने 90.00 की औसत से 1,710 रन बनाये। जिसमें 291 रनों की लंबी पारी शामिल थी। उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाकर एक एक ऐसा रिकार्ड बनाया जो अगले तीन दशक तक बना रहा।

अरविंदा डिसिल्वा - श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा ने साल 1997 में जमकर रन बनाते हुए 11 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 76.25 की औसत से 1,220 रन बनाए। 168 रनों के उच्चतम स्कोर के साथ, डिसिल्वा ने 7 शतक और 2 अर्धशतक लगाये थे।

सचिन तेंदुलकर - वहीं साल 2010 में भारत के सचिन तेंदुलकर ने ने 14 टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 3 बार नाबाद रहकर 78.10 की बेहतरीन औसत से 1,562 रन बनाए। 214 रनों की कप्तानी पारी उन्होंने खेली। 55.90 की स्ट्राइक रेट के साथ सचिन ने इस दौरान 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाये।

राष्ट्रमण्डल खेल 2026 - डिस्कस थ्रो में भारत की सीमा को मिला कांस्य

ग्लासगो । भारत की सीमा कालीरामना ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमण्डल खेलों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सीमा ने महिलाओं के वर्ग में विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल के दूसरे राउंड में 57.32 मीटर का थ्रो किया और फिर तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी हासिल कर ली। यही वह निर्णायक थ्रो था जिसने उन्हें पदक की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा। इसके बाद, सीमा के लगातार तीन प्रयास फाउल रहे। जिसके बाद उनकी पदक की उम्मीदें प्रतिद्वंद्वियों के प्रदर्शन पर निर्भर थीं। वहीं कैमरून की मोनी नोरा आतिम को कांस्य पदक के लिए 58.65 मीटर से आगे थ्रो करना था पर वह ऐसा करने में असफल रहीं। जैसे ही उनका अंतिम प्रयास समाप्त हुआ, सीमा को कांस्य मिलन पक्का हो गया। मुकाबले में भारत की दूसरी डिस्कस थ्रोअर निधि रानी ने 57.10 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए चौथे स्थान पर रहते हुए पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। जमैका की सामंथा हॉल ने 61.66 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता। सीमा के लिए ये पदक इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस एथलीट ने अपने बेटे रुद्र के जन्म के महज 11 महीने बाद पेशेवर खेल में वापसी करते हुए देश के लिए ये पदक जीता है। मातृत्व के बाद अपने शरीर को दोबारा प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाने के लिए उन्होंने लंबा और कठिन संघर्ष किया। फिटनेस, ताकत और तकनीक हासिल करने में उन्हें कई महीने लगे, जो उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सीमा केवल एक अंतरराष्ट्रीय एथलीट नहीं हैं, बल्कि भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी भी कर रही हैं।

कार्यालय नगरपालिका परिषद बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र) 481001

दूरभाष क्रमांक 07632-241318/247101 ईमेल- cmobalaghat@mpurban.gov.in

क्रमांक / स्वास्थ्य शाखा/2026/5667 बालाााट, तारीख 30/07/2026

सार्वजनिक सूचना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के नियम 39 के तहत शहरी क्षेत्रों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरीय निकायों व शहरी समूहों के उत्तदायित्व निर्धारित किये गये है, तथा कचरा फैलाने या नियमों के उपबंधों का अनुपालन न करने वालों के विरुध्द स्थल पर ही जुर्माना / शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अत: भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, निर्माण एवं विध्वंस नियम 2025, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 एवं म.प्र. नगर पालिका (जलै प्रदाय एवं मल-जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये अपशिष्ट पदार्थ) के अधिनियम 2020 उपनियम 02 प्रदत्त शक्तियां अनुसार एवं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करने एवं नगर को स्वच्छ बनाये जाने एवं नागरिकों को जागरुक करने एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय को उच्च स्तर प्रदान करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप कार्यवाही हेतु अलग अलग कृत्य के लिए अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है।

क्र.	कृत्य का प्रकार	अधिरोपित अर्थदंड (रु.में)
01	नगरीय सीमा क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों द्वारा खुले में कचरा फेंकने एवं चार डस्टबीन (हरा-जैविक अपशिष्ट, नीला-सुखा अपशिष्ट, लाल-सेनेटरी अपशिष्ट, काला-विशेष देखभाल अपशिष्ट) का उपयोग न करने पर।	500/-
02	मेडिकल, क्लीनिक, अस्पताल इत्यादि प्रतिष्ठान अपना मेडिकल वेस्ट स्वयं निष्पादन करें, ऐसा नहीं करने पर	न्यूनतम- 1000/- अधिकतम - 5000/-
03	घर-घर कचरा संग्रहण के समय कचरा पृथक-पृथक न करने पर।	250/-
04	डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क व्यवसायिक क्षेत्र से सालाना	1080/-
05	डोर टू डोर कचरा संग्रहण से आवासीय क्षेत्र सालाना उपभोक्ता शुल्क ।	720/-
06	औद्योगिक इकाईयो से सालाना उपभोक्ता शुल्क	1440/-
07	शासकीय एवं अर्ध्यशासकीय सालाना उपभोक्ता शुल्क	720/-.
08	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2022 के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में नियम 11 में उप नियम (01) के पश्चात् उप नियम अत: स्थापित किया जाएगा (झ क) कोई उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी तारीख 01 जुलाई 2025 से उप नियम (01) के अधीन निम्लिखित जानकारी उपलब्ध करवाए प्लास्टिक पैकेजिंग पर बार कोड या क्विक रिस्पोंस कोड होना आवश्यक है. अमानक पॉलीथीन प्लास्टिक प्रतिबंधित अधिनियम 31 दिसम्बर 2022 से 120 माईक्रोन कर दी गई है। 1 जुलाई 2022 से पोलिस्टिरीन और विस्तारीत पोलिस्टिरीन समेत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंण्डारण, ऋय, विक्रय, परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया. है। कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो जप्ती कर जुर्माना एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित को 5 साल कारावास की कार्यवाही प्रस्तावित की जात सकती है।	न्यूनतम- 1000/- अधिकतम - 25000/-
09	नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन एवं तोडे हुवे भवनों का अनुपयोगी मलबे के निपटान हेतु ट्रैचिंग ग्राउंड रेंगाटोला बालाघाट में प्रसंस्करण ईकाई स्थापित की गई है. इस हेतु निकाय के कर्मचारी श्री दीपक मोगरे, मो.नं. 7566540848 पर संपर्क कर निर्धारित शुल्क 500/- प्रति ट्रिप जमा कर सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। मकान निर्माण विध्वंस सामग्री /रोड नाली /सडक एवं सार्वजनिक स्थानों पर फेकने अथवा 48 घंटे से अधिक रखे जाने पर	1000/-
10	नगरीय सीमा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस कार्य को ग्रीन नेट से कवर करना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा	500/-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट

एक साल से मानदेय नहीं, अब काम भी छिनने का डर, ग्राम सामाजिक एनीमेटरों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सामाजिक अंकेक्षण का कार्य केवल प्रशिक्षित वीएसए से कराने की मांग, बाहरी एजेंसियों को जिम्मेदारी देने का विरोध

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) का कार्य वर्षों से कर रहे ग्राम सामाजिक एनीमेटरों ने अब अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंता जताई है। एक ओर लगभग एक वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य बाहरी एजेंसियों एवं अन्य संस्थाओं को सौंपे जाने की चर्चाओं ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को ग्राम विकास सामाजिक एनीमेटर संघ, बालाघाट के बैनर तले जिले के विभिन्न विकासखंडों से बड़ी संख्या में ग्राम सामाजिक एनीमेटर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि केंद्र एवं राज्य शासन की सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण केवल पूर्व से चयनित एवं प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनीमेटरों (वीएसए) से ही कराया जाए तथा उनके रोजगार और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

जिला मुख्यालय पहुंचे एनीमेटरों ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन ने वर्षों पहले ग्राम स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम सामाजिक एनीमेटरों का चयन किया था। चयन के बाद उन्हें विधिवत प्रशिक्षण देकर मनरेगा सहित केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व सौंपा गया। पिछले कई वर्षों से यह एनीमेटर गांव-गांव जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन, दस्तावेजों का परीक्षण, लाभार्थियों से चर्चा, ग्रामसभा में सामाजिक अंकेक्षण तथा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब उन्हीं की सेवाओं की अनदेखी की जा रही है। संघ की ओर से लालबर्रा विकासखंड की चौरेश्वरी बोपचे, कैलाश डेहरे सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बालाघाट जिले में करीब 160 ग्राम सामाजिक एनीमेटर कार्यरत हैं। इनमें अधिकांश पिछले पांच से छह वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें पिछले लगभग एक वर्ष से मानदेय नहीं मिला है। कई एनीमेटरों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक शासन के लिए काम करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और स्थायी रोजगार का रास्ता खुलेगा, लेकिन अब शासन सामाजिक अंकेक्षण का कार्य अन्य संस्थाओं को देने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। एनीमेटरों का कहना है कि वर्तमान में यह जानकारी मिल रही है कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जन अभियान परिषद अथवा अन्य बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने की तैयारी चल रही है। यदि ऐसा हुआ तो वर्षों से प्रशिक्षित और अनुभवी ग्राम सामाजिक एनीमेटरों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन ने उनके प्रशिक्षण पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। वर्षों के अनुभव के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रक्रियाओं और सामाजिक अंकेक्षण की तकनीकी बारीकियों को समझा है। ऐसे में यदि नए लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाती है तो शासन को फिर से प्रशिक्षण पर समय और धन खर्च करना पड़ेगा, जबकि पहले से प्रशिक्षित वीएसए पूरी तरह सक्षम हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड का मिलान करना नहीं है, बल्कि ग्रामसभा के माध्यम से आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना और किसी भी प्रकार की अनियमितता को उजागर करना है। यह कार्य स्थानीय परिस्थितियों, ग्रामीण व्यवस्था और शासकीय योजनाओं की गहरी जानकारी रखने वाले प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनीमेटर ही प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। बाहरी एजेंसियों या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया सामाजिक अंकेक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा और उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। संघ ने यह भी कहा कि ग्राम सामाजिक एनीमेटर केवल मनरेगा तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने समय-समय पर अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांवों में जाकर लाभार्थियों से सीधे संवाद करना, निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण करना, दस्तावेजों और भुगतान का मिलान करना तथा ग्रामसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल रहा है। उनकी मेहनत के कारण कई स्थानों पर योजनाओं में पारदर्शिता आई और अनियमितताओं पर अंकुश लगा। एनीमेटरों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने का प्रयास किया, लेकिन अब रोजगार छिनने की आशंका ने उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। उनका कहना है कि यदि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किसी अन्य संस्था को सौंप दिया गया तो जिले के करीब 160 और प्रदेशभर के हजारों प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनीमेटरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि केंद्र एवं राज्य शासन की सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण केवल पूर्व से चयनित एवं प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनीमेटरों (वीएसए) से ही कराया जाए। किसी भी योजना का सोशल ऑडिट बाहरी एजेंसियों, निजी संस्थाओं अथवा अप्रशिक्षित व्यक्तियों को न दिया जाए। साथ ही पिछले एक वर्ष से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए, ग्राम सामाजिक एनीमेटरों को नियमित रूप से कार्य उपलब्ध कराया जाए तथा उनके अनुभव और सेवाओं का उपयोग शासन की अन्य योजनाओं में भी किया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। एनीमेटरों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल अपने रोजगार के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि शासन इस विषय की गंभीरता को समझते हुए वर्षों से प्रशिक्षित ग्राम सामाजिक एनीमेटरों के हित में उचित निर्णय लेगा, ताकि सुशासन की भावना मजबूत हो और शासन की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रभावी ढंग से जारी रह सके।

25 जुलाई से लागू हुई मर्री टोल प्लाजा की नई दरें, NHAI ने जारी की संशोधित शुल्क सूची

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बालाघाटङ्कगोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-543) स्थित मर्री टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क (टोल टैक्स) की नई दरें लागू कर दी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना तथा NHAI मुख्यालय के नीति-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद संशोधित दरें 25 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। नई दरें NH-543 के किलोमीटर 0+000 से 41+210 (डिजाइन लंबाई 41.210 किमी) तक के बालाघाट-गोंदिया खंड पर स्थित मर्री टोल प्लाजा पर लागू होंगी। संशोधित शुल्क के अनुसार कार, जीप, वैन एवं हल्के मोटर वाहन के लिए एकल यात्रा शुल्क 95 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा 140 रुपये तथा 50 यात्राओं के मासिक पास की दर 3,100 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं हल्के वाणिज्यिक वाहन एवं मिनी बस के लिए एकल यात्रा शुल्क 150 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी के लिए 225 रुपए, 50 यात्राओ के मासिक पास के लिए 5010 रुपए की दर निर्धारित की गई है। बस एवं दो एक्सल ट्रक के लिए एकल यात्रा के 315 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए 470 रुपए एवं 50 मासिक यात्राओं के लिए 10 हजार 495 रुपए की दर निर्धारित की गई है। तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन के लिए एकल यात्रा के 345 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए 515 रुपए एवं 50 मासिक यात्राओं के लिए 11 हजार 450 रुपए की दर निर्धारित है। 4 से 6 एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों के लिए एकल यात्रा के 495 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए 740 रुपए एवं 50 मासिक यात्राओं के लिए 16 हजार 455 रुपए की दर निर्धारित है। सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए एकल यात्रा के 600 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए 900 रुपए एवं 50 मासिक यात्रा के लिए 20 हजार 35 रुपए की दर निर्धारित की गई हैं। स्थानीय गैर व्यावसायिक वाहनों में कार, जीप, वैन,एवं हल्के मोटर वाहन के लिए 45 रुपए, हल्के वाणिज्यिक वाहन एवं मिनी बस के लिए 75 रुपए, बस, ट्रक टू एक्सल के लिए 155 रुपए, 3 एक्सल वाणिज्यिक वाहन के लिए 170 रुपए, 4 से 6 एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 245 रुपए एवं सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए 300 रुपए की दर निर्धारित है। NHAI ने स्थानीय निवासियों को भी राहत दी है। मर्री टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए 3,075 रुपये का वार्षिक पास निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पंजीकृत गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए रियायती एकल यात्रा शुल्क भी लागू रहेगा। प्राधिकरण ने सभी वाहन चालकों एवं परिवहन संचालकों से ख्नस्ञ्जड्डद्द के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान करने की अपील की है, ताकि टोल प्लाजा पर यातायात सुगम और निर्बाध बना रहे। NHAI के अनुसार संशोधित शुल्क सूची टोल प्लाजा पर प्रदर्शित कर दी गई है तथा नई व्यवस्था के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बिना नए तथ्यों के अभियोजन मंजूरी पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी पहले ही मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर चुका है, तो उसी साक्ष्य के आधार पर उस निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा तभी संभव है, जब पहले उपलब्ध न रहे कोई नए तथ्य या नए साक्ष्य सामने आए हों।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राजस्थान सरकार की अपील खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि केवल पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर राय बदलना कानून सम्मत नहीं है और इससे मंजूरी न देने के पूर्व आदेश की समीक्षा का आधार नहीं बनता। मामला वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा डॉ. देव कांत मीणा के खिलाफ की गई ट्रैप कार्रवाई से जुड़ा है। उन पर घुटने की सर्जरी के लिए मरीज के परिजन से रिश्वत मांगने का आरोप था। हालांकि जांच के बाद कार्मिक विभाग को रिश्वत मांगने या स्वीकार करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले और मार्च 2018 में अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। इस निर्णय को प्रधान सचिव और मुख्य सचिव ने भी मंजूरी दी थी।

बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बिना किसी नए साक्ष्य के मामले पर दोबारा विचार किया गया और अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पुनर्विचार को अवैध ठहराते हुए मंजूरी रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा मंजूरी से इनकार किए जाने के बाद बिना किसी नए तथ्य के मामले को दोबारा खोलना उचित नहीं था। अदालत ने कहा कि इससे संबंधित अधिकारी को अनावश्यक रूप से न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़े। पीठ ने यह भी कहा कि यदि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दो अलग-अलग राय संभव हों, तो सरकारी कर्मचारी के पक्ष में जाने वाली राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आपराधिक मुकदमे में दोष तभी सिद्ध माना जाता है जब आरोप संदेह से परे साबित हों। इसी आधार पर अदालत ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 50-50 हजार रुपये, कुल एक लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया।

तीसरी बार टला ई-वे बिल में बदलाव, उद्योग जगत के दबाव के आगे झुकी सरकार

नई दिल्ली । वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने ई-वे बिल प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों को तीसरी बार टाल दिया है। पहले यह व्यवस्था 15 जून से लागू होनी थी, बाद में इसे 1 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया. अब अगली सूचना तक के लिए इस बदलाव को स्थगित कर दिया गया है। जीएसटी ने स्पष्ट किया है, 9 जून और 17 जून को जारी एडवाइजरी के तहत प्रस्तावित बदलाव फिलहाल लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही संबंधित एडवाइजरी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी वापस लिए जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले के पीछे उद्योग जगत का तीव्र विरोध प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऑटो कंपोनेंट, ई-कॉमर्स, ईपीसी और जटिल सप्लाई चेन वाले उद्योगों ने कहा था कि नए नियम लागू करने के लिए ईआरपी सिस्टम,एपीआई इंटीग्रेशन, मास्टर डेटा और सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव की जरूरत होगी. प्रस्तावित बदलावों में शिप-टू जीएसटीएन को अनिवार्य करना और वॉलेंटरी ई-वे बिल क्लोजर जैसी नए बदलाव शामिल थे.उद्योग संगठनों का कहना था, इन बदलावों का मौजूदा ई-इनवॉयस और ई-वे बिल प्रणाली के साथ समन्वय करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार द्वारा उद्योग जगत की व्यावहारिक चिंताओं को स्वीकार करने का संकेत है।

न्यायिक सेवा में वकालत की अनिवार्य शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सीधी भर्ती के लिए 3 वर्ष की वकालत को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की अनिवार्य वकालत की शर्त में छूट देने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने महत्वपूर्ण मामले पर विभिन्न पक्षों के वकीलों, हस्तक्षेपकर्ताओं और न्यायालय मित्र की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसमें निचली न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए कम से कम तीन वर्ष के वकालत अनुभव को अनिवार्य किया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह शर्त प्रतिभाशाली विधि स्नातकों को पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा में आने से हतोत्साहित करेगी और युवा अभ्यर्थियों के लिए अनावश्यक बाधा साबित होगी। सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील पिंकी आनंद ने सुझाव दिया कि भर्ती से पहले वकालत को अनिवार्य करने के बजाय, नियुक्ति के बाद न्यायिक प्रशिक्षण को अधिक मजबूत और देशव्यापी रूप से समान करना चाहिए।

खंडवा में नदी के टापू पर 11 घंटे फंसे चार लोग, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में दो नदियों के संगम पर पिकनिक के दौरान टापू पर फंसे चार लोगों को राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एसडीईआरएफ) ने शुक्रवार तड़के करीब 11 घंटे के चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद सकुशल बचा लिया। बचाए गए हुजेफा हामिद (40), मयंक (16), अली असगर (35) और आयुष (18) गुरुवार को जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सुक्ता-आवना नदियों के संगम स्थल हांडीकुंडी में पिकनिक मना रहे थे। तेज बारिश से जलस्तर अचानक बढ़ने पर वे टापू पर फंस गए। शाम 6ः15 बजे सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती मोटरबोट प्रयास तेज बहाव के कारण जोखिमपूर्ण रहा, जिसके बाद बचाव दल ने जलस्तर कम होने का इंतजार किया। इस दौरान, ड्रोन की मदद से टापू तक लाइफ जैकेट, भोजन और पेयजल पहुंचाया गया, और मोबाइल से लगातार संपर्क कर उनका मनोबल बनाए रखा गया। जलस्तर में आंशिक कमी आने पर, सुरक्षा रस्सियों से नियंत्रित मोटरबोट के जरिए शुक्रवार तड़के 4ः45 बजे सभी चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जमानत मामले में जज से संपर्क की कोशिश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा— आज न्यायिक इतिहास का काला दिन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक असाधारण स्थिति सामने आई, जब न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने जमानत आदेश पारित करने से पहले स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। उन्होंने कोडीन युक्त कफ सिरप प्रकरण में गिरफ्तार आरोपितों की ओर से दाखिल 80 जमानत अर्जियों को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया।

मामला उस समय गंभीर हो गया, जब न्यायालय के संज्ञान में आया कि एक पक्षकार ने जमानत याचिकाओं के संबंध में न्यायमूर्ति से संपर्क करने का प्रयास किया था। इस घटना को न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आज न्यायालय के इतिहास का काला दिन है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की निष्पक्षता और उस पर जनता का विश्वास सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनुचित कोशिश या प्रभाव की आशंका को भी गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जाए। इसी उद्देश्य से सभी 80 जमानत अर्जियां मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजी गई हैं, ताकि वे नई पीठ नामित कर सकें।

यह मामला कोडीन युक्त सिरप से जुड़े प्रकरण में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत याचिकाओं से संबंधित है। न्यायालय के इस कदम को न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायिक मर्यादा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिहार के मंत्री का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, छह महीने बाद भी मंत्री कैसे बने हुए हैं?

-क्या नई सरकार बनने से छह महीने की अवधि फिर से शुरू हो जाती है?

नई दिल्ली। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर संवैधानिक विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संविधान कहता है कि गैर-विधायक या गैर-एमएलसी व्यक्ति सिर्फ छह महीने तक ही मंत्री रह सकता है, तो फिर दीपक प्रकाश अब तक मंत्री कैसे बने हुए हैं? क्या सीएम बदलने और नई सरकार बनने से छह महीने की अवधि फिर से शुरू हो जाती है? या यह पूरा मामला संविधान की भावना के खिलाफ है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है, लेकिन वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर वह छह महीने के अंदर निर्वाचित या मनोनीत नहीं होता है तो उस व्यक्ति को मंत्री पद छोड़ना होगा। संविधान इस अवधि को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं देता। बता दें दीपक प्रकाश ने 20 नवंबर 2025 को मंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय वह न विधायक थे और न ही विधान परिषद के सदस्य। इस हिसाब से उन्हें 20 मई 2026 तक किसी एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसी बीच बिहार में राजनीतिक बदलाव हुआ। नीतीश कुमार सरकार हट गई और 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नीत सरकार बनी। इस नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर मंत्री बना दिया गया। अब विवाद यह है कि क्या नई सरकार बनने से छह महीने दोबारा शुरू हो जाते हैं? यही सबसे बड़ा कानूनी सवाल है। बिहार सरकार का अप्रत्यक्ष तर्क यही माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के साथ नई नियुक्ति हुई, इसलिए छह महीने की नई अवधि लागू होगी, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा मानना संविधान की भावना के खिलाफ होगा। अगर ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी सरकार हर छह महीने में मंत्री को दोबारा शपथ दिलाकर बिना चुनाव लड़ाए सालों तक मंत्री बनाए रख सकती है।

कोर्ट केवल एक बार की अस्थायी छूट देता है। छह महीने पूरे होने के बाद बिना विधायक बने फिर से मंत्री बनाना संविधान की भावना के विपरीत है। ऐसा करना संविधान के साथ छल माना जाएगा यानी अदालत ने साफ कर दिया था कि छह महीने की सीमा से बचने के लिए बार-बार शपथ नहीं दिलाई जा सकती। यहीं पर कानूनी बहस शुरू होती है। दीपक प्रकाश के समर्थकों का तर्क हो सकता है कि यहां केवल दोबारा शपथ नहीं हुई, बल्कि पूरी सरकार ही बदल गई।

हाईकोर्ट के जज कृष्ण कोडीन कफ सिरप मामले की सुनवाई से हुए अलग

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल समेत 75 आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। फैसला सुरक्षित रखने से पहले वादकारी पक्ष की ओर से पीठासीन न्यायाधीश तक निजी माध्यमों से संपर्क साधने की कोशिश की गई। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद जज ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन करार दिया। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश के सामने भेजकर किसी अन्य पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखने से पहले न्यायाधीश तक निजी पहुंच बनाने की कोशिश न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर गंभीर आघात है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने साफ किया कि यदि ऐसे में फैसला किसी के पक्ष में आता है, तो निष्पक्षता पर अनावश्यक संदेह पैदा हो सकता है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए।

कोर्ट ने कहा लंबित मामले में न्यायाधीश तक निजी संपर्क का प्रयास न्यायिक आचरण, अधिवक्ता नैतिकता और संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक की संवैधानिक गारंटी है और इसे प्रभावित करने की कोशिश न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। इसलिए इन मामलों को दोबारा इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध न करने का निर्देश दिया है। मामले के आरोपियों ने पहले प्राथमिकी रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ का रुख किया था, लेकिन सभी याचिकाएं खारिज हो गई थीं। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग भी ठुकरा दी। अब गिरफ्तार आरोपियों की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसके दौरान यह अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आई।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

-बड़ी बेंच को मामला भेजा जाए या नहीं, सरकार ने कहा- संविधान पीठ को भेजा जाए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह तय करने संबंधी आदेश सुरक्षित रख लिया कि मामले को संविधान पीठ (बड़ी बेंच) के पास भेजा जाए या नहीं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि मामला संविधान पीठ को भेजा जाए, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा इस विषय पर कानून बनाने की संसद की विधायी शक्ति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ द्वारा दिया गया फैसला, जिसमें संसद द्वारा कानून बनने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की समिति के माध्यम से करने की अंतरिम व्यवस्था तय की गई थी, स्वयं कई संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि यह माना जाए कि उस निर्णय ने पूरे क्षेत्र को अंतिम रूप से नियंत्रित कर दिया है, तो संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि अनूप बरनवाल का फैसला केवल अंतरिम व्यवस्था प्रदान करता था और उसमें यह अनिवार्य संवैधानिक सिद्धांत स्थापित नहीं किया गया था कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का होना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाओं में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, जिनमें यह शामिल है कि क्या अनुच्छेद 324 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को केवल इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया जा सकता है कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश जैसे किसी बाहरी संवैधानिक पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया। साथ ही यह भी कि क्या अदालतें किसी कानून की समीक्षा करते समय कार्यपालिका के दुर्भावनापूर्ण आचरण या सत्ता के दुरुपयोग का पूर्वानुमान लगा सकती हैं।

केंद्र ने कहा कि किसी संवैधानिक अदालत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री या कार्यपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत कार्य करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद की सुनवाई मौजूदा पीठ करेगी या इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा।

बालाघाट
शनिवार 01 अगस्त 2026
दक्षिण सतपुड़ा
राजनीति | समाज | देशकाल
और गांव कनेक्शन की खबरें

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia
epaper.balaghatexpress.in
E-mail: balaghatexpress@gmail.com

चावल घोटाले में पूर्व मंत्री व भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे का भतीजा अविनाश कावरे गिरफ्तार

न्यायालय ने दी 3 अगस्त तक पुलिस रिमांड एसआईटी के रडार पर ओर भी गिरफ्तारियां संभावित

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले अंतरराज्यीय चावल सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस और विशेष जांच दल का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटे जाने वाले फ ोर्टिफाइड चावल को ब्लैक मार्केट, एथेनॉल प्लांटों और बीयर कंपनियों में खपाने के इस बड़े फर्जीवाड़े में अब तक कुल २६ ट्रकों को जब्त किया जा चुका है। वारासिवनी से उजागर हुए इस घोटाले में पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे का भतिजा अविनाश कावरे और एक नए आरोपी गोपाल ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं मामले की परतें खोलने के लिए गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

दो नए आरोपी गिरफ्तार, पूर्व आरोपी की भी ली रिमांड

थाना वारासिवनी में दर्ज अपराध क्रमांक २७२/२६ भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१६ (३),३३६(३) ,३४० (२) ,३३८ एवं ३/५ के तहत दर्ज में कार्यवाही करते हुए पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने दो नये आरोपी जिसमें पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे का भतिजा अविनाश कावरे पिता स्व.सरोज कावरे २८ वर्ष निवासी बघोली एवं गोपाल ठाकुर पिता हीरालाल ठाकुर ५४ वर्ष निवासी आवलाझरी दोनों आरोपियों को धर दबोचा कर ३१ जुलाई को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इसके साथ ही प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी कुंजबिहारी पटले निवासी नैतरा जो वर्तमान में जेल में था उसकी इन दो नए आरोपियों के साथ आमने सामने पूछताछ करने के लिए ३ अगस्त तक की पुलिस रिमांड न्यायालय से प्राप्त की गई है।

ऐसे चलता था यह दोहरा मुनाफा कमाने वाला खेल

जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से जो फ ोर्टिफाइड चावल गरीबों के लिए आवंटित किया जाता था उसे ट्रकों में भरकर एथेनॉल प्लांटों और बीयर कंपनियों को भेज दिया जाता था। इतना ही नहीं इस चावल को महंगे दामों पर खुले बाजार के राइस मिलर्स को बेचा जाता था। राइस मिलर्स इसी सरकारी चावल को री.साइकिल कर कस्टम मिलिंग के नाम पर वापस सरकारी गोदामों में जमा करा देते थे। इस तरह यह सिंडिकेट गरीबों के राशन की हेराफेरी कर दोहरा मुनाफा कमा रहा था।

एसआईटी के रडार पर कई बड़े सरगना जांच जारी

अब तक २६ ट्रकों की जब्ती यह साफ दर्शाती है कि यह घोटाला किस कदर विशाल रूप ले चुका है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस और एसआईटी मुख्य सरगनाओं उनकी बेनामी संपत्तियों और इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य राइस मिलर्स के बारे में सघन पूछताछ कर रही है। एसआईटी सूत्रों के अनुसार सिंडिकेट से जुड़े कई बड़े नाम जांच दल के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और भी वाहनों की जब्ती के साथ साथ कई गिरफ्तारियां संभव हैं। एसआईटी तेजी से साक्ष्य जुटा रही है ताकि इस अंतरराज्यीय गिरोह का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके।

अब घर के बाहर खड़ी कार भी सुरक्षित नहीं, भटेरा से टाटा पंच कार चोरी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब चोरों ने अपने निशाने का दायरा भी बढ़ा दिया है। पहले सूने मकान, दुकान और दोपहिया वाहन चुराने वाले बदमाश अब घरों के सामने खड़ी चारपहिया गाडियों पर भी हाथ साफ करने लगे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा इलाके से टाटा पंच कार चोरी होने की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद शहरवासियों में भय का माहौल है और लोग अपने घरों के बाहर वाहन खड़ा करने से भी घबराने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार भटेरा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसने 30 जुलाई की रात अपनी टाटा पंच कार घर के सामने खड़ी की थी। सुबह जब वह बाहर निकला तो कार मौके से गायब थी। वाहन की काफी तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से लैस थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने सुनियोजित तरीके से नकली चाबी या किसी तकनीकी माध्यम का उपयोग कर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। जिस तरह बिना किसी शोर-शराबे के कार गायब हुई है, उससे यह भी माना जा रहा है कि घटना में पेशेवर वाहन चोर गिरोह का हाथ हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली थाना प्रभारी अजय गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों तथा पेट्रोल पंपों सहित विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी के बाद वाहन किस दिशा में ले जाया गया और वारदात में कितने लोग शामिल थे। इसके साथ ही जिले की सीमाओं से लगे थानों और पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी वाहन की जानकारी भेजी गई है। इस घटना ने शहर में वाहन सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि घर के सामने खड़ी चारपहिया गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा किया जाए। लोगों ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने और वाहन चोर गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी अजय गुर्जर ने बताया कि वाहन चोरी की शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर चोरी गई कार बरामद कर ली जाएगी। फिलहाल एक दिन बीत जाने के बाद भी चोरी हुई टाटा पंच कार का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस की जांच जारी है, जबकि इस घटना ने शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोहों की मौजूदगी की आशंका को और मजबूत कर दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर यह हाई-प्रोफाइल वाहन चोरी का खुलासा कब तक हो पाता है।

भीमगढ़ बांध के दो गेट खोले गये, वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना

वैनगंगा नदी के तटीय क्षेत्र के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। सिवनी जिले में स्थित संजय सरोवर परियोजना (भीमगढ़ बांध) का जलस्तर निर्धारित स्तर के करीब पहुंचने पर अतिरिक्त जल निकासी के लिए शुक्रवार 31 जुलाई को सुबह 11=30 बजे बांध के दो गेट खोले गये हैं। जिसके कारण वैनगंगा नदी में जलस्तकर बढ़ने की संभावना है। बालाघाट जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है।

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार भीमगढ़ बांध के गेट क्रमांक 5 एवं 6 को एक-एक मीटर तक खोला जाएगा। दोनों गेटों से कुल 265 क्यूमेक्स (9,340 घनफीट प्रति सेकंड) की दर से अतिरिक्त पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा जाएगा। वर्तमान में भीमगढ़ बांध का जलस्तर 516.85 मीटर दर्ज किया गया है और जलस्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने नदी तटीय क्षेत्रों एवं निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे नदी में प्रवेश न करें तथा अनावश्यक रूप से नदी किनारे या जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।

बालाघाट जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा एवं निगरानी के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए नागरिक कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07632-240102 पर संपर्क कर सकते हैं।

लखनवाड़ा रेलवे ट्रेक पर मिला बुजुर्ग का शव

पदमेश न्यूज। कटंगी। शुक्रवार को जिले के कटंगी थाना अंतर्गत लखनवाड़ा के रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिला। जिसकी पहचान, ग्राम पंचायत कोसमी निवासी डालीराम भगत (50) के रूप में की गई। घटना के बाद से परिजनों और गांव में शोक का माहौल है।घटना की जानकारी मिलने के बाद कटंगी पुलिस, रेलवे ट्रेक पहुंची और बुजुर्ग डालीराम के शव को बरामद कर उसे पीएम के लिए कटंगी अस्पताल लाया। यहां परिजनों की मौजूदगी में शव पंचनामा कार्रवाई के उपरांत शव का पीएम करवाकर, परिजनों को शव सौंप दिया।

बेटी की परीक्षा से संबंधित काम के लिए आया था बालाघाट

प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को बुजुर्ग डालीराम भगत, बेटी की परीक्षा से

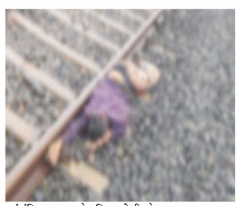

संबंधित काम के लिए बेटी के साथ बालाघाट आया था। यहां से बेटी, अपनी सहेली के साथ गांव वापस लौट गई लेकिन डालीराम नहीं लौटा था। बताया जाता है कि गुरूवार की शाम डालीराम, बालाघाट से ट्रेन से गांव वापस जाने निकला था। जिसे लखनवाडा में उतरना था, जहां से वह अपने गांव कोसमी जाता, लेकिन रात में घर नहीं पहुंचा।शुक्रवार, उसकी तलाश किए जाने पर, उसका शव रेलवे स्टेशन के ट्रैक में देखा गया।

ट्रेन की चपेट में आने से मौत के लगाए जा रहे कयास

हालांकि यह हादसा कैसे हो गया फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं की 30 जुलाई की रात में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई होंगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह हादसा ट्रेन से उतरते समय या चलती ट्रेन से गिरने के दौरान हुआ है। कटंगी पुलिस ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पुलिस मामले की जांच हर एंगल से करेगी। कटंगी रेलवे स्टेशन से पता चला कि गोंदिया से कटंगी ट्रेन के पायलेट ने रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की सूचना, स्टेशन में दिया था।

बैनगंगा पुल पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वारासिवनी रोड स्थित बैनगंगा नदीके पुल पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया। यह युवक खिलेंद्र पिता राजू दशरीये 30 वर्ष ग्राम कनकी थाना लालबर्रा निवासी है। जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है । प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कनकी निवासी खिलेंद्र दशरीये मिस्त्री का कार्य करता है। 30 जुलाई की रात करीब 8=30 बजे खिलेंद्र किसी काम से कनकी में साइकिल में बालाघाट जा रहा था। इसी दौरान बैनगंगा नदी के पुल पर सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।हादसे में खिलेंद्र मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया।जहां उसका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल पुलिस ने खिलेंद्र का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी है।

मिर्गी का दौरा पड़ने से खेत में गिरे युवक की मौत

गढ़ी थाने के मुरेंडा गांव की घटना

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरेंडा में शुक्रवार को एक 19 वर्षीय युवक की खेत में मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद मौत हो गई। सूचना मिलने पर गढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतक युवक विदेसिह पिता जगदीश धुर्वे शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विदेसिंह धुर्वे अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता था। परिवार में माता-पिता के अलावा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन हैं।जिनका विवाह हो चुका है। बताया गया कि विदेसिंह अपने रिश्ते के चाचा एवं ग्राम सरपंच अमरलाल धुर्वे के यहां रहकर उनके साथ खेती का कार्य करता था। बताया गया है कि विदेसिंह को लंबे समय से मिर्गी की बीमारी थी और उसका उपचार भी चल रहा था।जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे विदेसिंह गांव के एक 12 वर्षीय बालक के साथ खेत गया था। इसी दौरान उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वह औंधे मुंह कीचड़ में गिर गया। बालक ने तत्काल घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन जब खेत पहुंचे तब तक विदेसिंह की मौत हो चुकी थी।घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस ग्राम मुरेंडा पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद खेत में गिरने से हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एण्ड पॉलिटेक्निक
बी.टेक. पॉलिटेक्निक
JOB SAHi
- कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
- माईनिंग इंजीनियरिंग
- सिविल इंजीनियरिंग
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
ADMISSION OPEN
नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों का Lateral Entry द्वारा बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा-बालाघाट
6262604111, 9425836824 www.satpudaengineeringcollege.com

आवश्यकता है
क्वार्क में पेज सेटिंग हेतु
कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता है
संपर्क करें-बालाघाट एक्सप्रेस
पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट